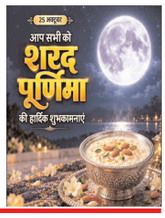
दैनिक
राष्ट्रीय जनभावना

RNI-MPHIN/2013/53761

वर्ष-3, अंक-29
इन्दौर, सोमवार
26 अक्टूबर 2026
पृष्ठ 8, मूल्य 2 रु.



जामिया में चुनाव की मांग पर छात्रों का प्रदर्शन

विरोध-प्रदर्शन के बीच कैंपस के गेट बंद, स्टूडेंट्स को रोकने पर विवाद, कई हिरासत में

नई दिल्ली । दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का रविवार को भी छात्र, चुनाव की मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के उस फैसले पर सवाल उठाए, जिसके तहत अचानक सभी क्लास ऑनलाइन कर दी गईं।

छात्रों का आरोप है कि यह कैंपस खाली कराने और स्टूडेंट यूनियन (छात्र संघ) को बहाल करने की उनकी मांग को दबाने की एक सोची-समझी चाल है। गेट नंबर 4 पर एंट्री पाबंदियों को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच बहस हो गई। जिन छात्रों के पास कॉलेज के रेगुलर आईडी कार्ड तो थे, लेकिन हॉस्टल आईडी नहीं थी, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया। इधर, पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने शनिवार को घोषणा की कि अगले आदेश तक सभी कोर्स ऑनलाइन मोड में चलेंगे।

कच्चा तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी, रूपए में गिरावट, महंगाई और बढ़ी ब्याज दर का असर

विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय-बाजार से निकाले 48,056 करोड़

मुंबई । विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय शेयर बाजार से निकासी का सिलसिला अक्टूबर महीने में भी जारी है। वरूड तेल की ऊंची कीमतों, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, महंगाई की चिंता और कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों के कारण विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय इक्विटी से 48,056 करोड़ रूपए की बिकवाली की है। हालांकि, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बिकवाली की रफ्तार में कमी आई और विदेशी निवेशकों दो कारोबारी दिनों में नेट बायर्स भी रहे, जिससे बाजार पर दबाव कुछ कम होने के संकेत मिले हैं।

अक्टूबर महीने में हुई यह बिकवाली पिछले महीने से भी ज्यादा रही। इससे पहले सितंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 35,861 करोड़ रूपए की नेट निकासी की थी।

2026 में कुल बिकवाली 3.08 लाख करोड़ पहुंची

साल 2026 में अब तक विदेशी निवेशकों की कुई कुल बिकवाली का आंकड़ा 3.08 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। यह बिकवाली साल 2025 के मुकाबले काफी ज्यादा है। पूरे 2025 के दौरान विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से कुल 1.66 लाख करोड़ रूपए निकाले थे। यानी 2026 के शुरुआती 10 महीनों ने ही पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है।

एफपीआई बिकवाली के कारण

विदेशी निवेशकों द्वारा की जा रही बिकवाली के कई कारण रहे हैं। इनमें मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़कर 114 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गई हैं। एनर्जी की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई है। 30,213 करोड़ के जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ ने बाजार की लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब कर लिया, जिससे शेयरों पर दबाव बढ़ा।

दुनिया पर कर्ज का पहाड़...

अमेरिका और चीन के बाद भारत की अर्थव्यवस्था पर भी कर्ज का दबाव, ब्याज भुगतान में बढ़ते खर्च से विकास योजनाओं और सरकारी खजाने पर बढ़ रहा भारी दबाव, भारत पर जीडीपी के 83.4 प्रतिशत तक पहुंचा सरकारी कर्ज...

- भारत में सरकारी राजस्व से प्राप्त आय का लगभग 40 प्रतिशत ब्याज और किस्त चुकाने में हो रहा है खर्च
- कर्ज के बोझ का असर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर रोजगार और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है भारी

323 लाख करोड़ के कर्ज से दबा भारत

● नई दिल्ली

दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक सरकारों को उधारी की बढ़ती लागत और ब्याज भुगतान की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस वैश्विक तस्वीर में भारत भी अछूता नहीं है। भारत पर केंद्र और राज्य सरकारों का कुल कर्ज देश की जीडीपी के 83.4 प्रतिशत के बराबर है। वहीं, कुल सरकारी कर्ज का अनुमान करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 323 लाख करोड़ रुपये बताया गया है। कर्ज के बोझ का असर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। भारत में सरकारी राजस्व से प्राप्त आय का लगभग 40 प्रतिशत ब्याज और किस्त चुकाने में खर्च हो रहा है। इस कारण भारत में विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। आज कर्ज अंतरराष्ट्रीय समस्या बन गया है।

दुनिया में सरकारी कर्ज के आकार के लिहाज से अमेरिका, चीन और जापान के बाद भारत का नाम भी बड़े कर्जदार देशों में शामिल है। हालांकि, किसी देश की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल कर्ज की कुल रकम से नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था का आकार, सरकार की कमाई, विकास दर और ब्याज चुकाने की क्षमता भी उतनी ही अहम होती है। फ्रांस में 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड करीब 5 प्रतिशत तक पहुंचने और जर्मनी में इसके 3.41 प्रतिशत रहने का उदाहरण बताता है कि एक ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी उधारी की लागत अलग-अलग हो सकती है। निवेशक जिस देश को कर्ज देने के बदले अधिक रिटर्न मांगते हैं, उसके लिए नई उधारी महंगी हो जाती है। भारत के संदर्भ में यह मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार को बुनियादी ढांचे, रेलवे, सड़क, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर लगातार खर्च करना होता है। यदि ब्याज भुगतान पर खर्च बढ़ता है, तो बजट में दूसरे मदों के लिए उपलब्ध गुंजाइश प्रभावित हो सकती है। हालांकि, इसका वास्तविक असर सरकार की राजस्व प्राप्तियों, खर्च की प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास की रफ्तार पर निर्भर करेगा।

अमेरिका पर भारत से 12 गुना से ज्यादा सरकारी कर्ज



उपलब्ध रिपोर्ट ने दिए गए अनुमानों के अनुसार, अमेरिका पर करीब 41.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 3,933 लाख करोड़ रुपये का सरकारी कर्ज है। चीन पर 22.5 ट्रिलियन डॉलर और जापान पर 8.7 ट्रिलियन डॉलर की देनदारी बताई गई है। भारत का अनुमानित सरकारी कर्ज 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। इस तुलना ने अमेरिका का सरकारी कर्ज भारत के अनुमान से 12 गुना से अधिक है। लेकिन केवल कुल रकम की तुलना से यह तय नहीं होता कि किस देश पर वित्तीय दबाव अधिक है।

कर्ज महंगा हुआ तो बजट पर पड़ेगा असर

सरकारें सरकारी बॉन्ड जारी करके बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और अन्य निवेशकों से धन जुटाती हैं। बदले में उन्हें निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज देना और अवधि पूरी होने पर मूल रकम लौटानी होती है। सरकार को पुराने कर्ज की अदायगी के लिए भी कई बार नई उधारी लेनी पड़ती है। बॉन्ड की कीमतें घटने पर उनकी यील्ड बढ़ सकती है। नई उधारी के समय ऊंची यील्ड सरकार के लिए अधिक ब्याज लागत का कारण बनती है। हालांकि, पहले से जारी सभी बॉन्ड पर ब्याज तुरंत नहीं बढ़ता, इसका असर कर्ज की अवधि और उसके पुनर्वित्त की जरूरत पर निर्भर करता है।

जीडीपी के मुकाबले भारत की स्थिति खराब

रिपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (जीडीपी) के 2026 के अनुमान के हवाले से भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के कुल कर्ज को जीडीपी का 83.4 प्रतिशत बताया गया है। तुलना के लिए अमेरिका का कर्ज-जीडीपी अनुपात 127 प्रतिशत, फ्रांस का 118 प्रतिशत और जापान का करीब 199 प्रतिशत बताया गया है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कर्ज का अनुपात अलग-अलग स्तर पर है। जापान का अनुपात भारत से काफी अधिक है, जबकि अमेरिका और फ्रांस में भी कर्ज अर्थव्यवस्था के आकार के मुकाबले ऊंचे स्तर पर है। फिर भी, अलग-अलग देशों की वित्तीय स्थिति में अंतर होता है। उनकी कर व्यवस्था, घरेलू निवेशकों की भूमिका, मुद्रा की स्थिति और कर्ज की औसत अवधि भी महत्वपूर्ण हैं।

केवल कर्ज नहीं, उसे चुकाने की क्षमता भी अहम

दुनिया में बढ़ते सरकारी कर्ज की चर्चा के बीच भारत की स्थिति को समझने के लिए कुल देनदारी के साथ उसके प्रबंधन पर भी नजर रखनी होगी। कर्ज का आकार, जीडीपी के मुकाबले उसका अनुपात, ब्याज भुगतान और सरकारी आय-ये सभी संकेतक मिलकर तस्वीर स्पष्ट करते हैं। भारत के सामने चुनौती आर्थिक विकास की जरूरतों को पूरा करने के साथ राजकोषीय संतुलन बनाए रखने की है। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और दूसरे बुनियादी ढांचे में निवेश भविष्य की वृद्धि को सहारा दे सकता है, लेकिन इसके साथ ब्याज भुगतान और सरकारी खर्च पर निगरानी भी जरूरी है। वैश्विक स्तर पर उधारी महंगी होने की स्थिति में कर्ज प्रबंधन और राजस्व बढ़ाने की रणनीति का महत्व और बढ़ जाता है।

देश	कर्ज (लाख करोड़)
अमेरिका	3,933
चीन	2,137.5
जापान	826.5
ब्रिटेन	418
फ्रांस	399
इटली	351.5
जर्मनी	332.5
भारत	323
कनाडा	275.5

हनीट्रैप में फंसा सेना का रिटायर्ड कैप्टन गिरफ्तार

अनजान महिला को खुफिया जानकारी भेजी 28 साल तक आर्मी में सर्विस कर चुका

वेल्लोर । तमिलनाडु के वेल्लोर में 52 साल के रिटायर्ड आर्मी अधिकारी बाबू को गिरफ्तार किया गया है। बाबू पर आरोप है कि उसने सेना से जुड़ी कई अहम जानकारियां लीक कीं। कनियामबाड़ी पुलिस के मुताबिक, बाबू ने व्हाट्सएप के जरिए एक अज्ञात महिला को सैन्य उपकरणों और इंडियन आर्मी से जुड़ी गोपनीय जानकारी भेजी। बाबू वेल्लोर के कोइलक्कम गांव का रहने वाला है। वह 28 साल तक इंडियन आर्मी की अलग-अलग शाखाओं में सेवा दे चुका है। उसने पिछले साल आर्मी की इक्विपमेंट डिवीजन से कैप्टन पद पर रिटायरमेंट लिया था। इसके बाद वह अपने गांव में रहने लगा।

जानकारी के मुताबिक, करीब एक साल पहले एक अज्ञात महिला ने बाबू से व्हाट्सएप पर संपर्क किया था। महिला ने पहले अनुचित बातचीत के जरिए उससे संबंध बनाए। इसके बाद वह धीरे-धीरे इंडियन आर्मी से जुड़ी जानकारी मांगने लगी। बाबू ने महिला की मांगी गई जानकारी उसे भेजी। जब उसे किसी जानकारी का पता नहीं होता था, तो वह फोन पर आर्मी के दफ्तरों से जानकारी लेता था। इसके बाद वह वह जानकारी महिला को भेज देता था।

सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिग्विजय बोले...

हिंदुत्व का सनातन धर्म से कोई लेना-देना नहीं



शाजापुर । मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शाजापुर में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि वे कभी हिंदुत्व के समर्थक नहीं रहे और न रहेंगे, क्योंकि हिंदुत्व का सनातन धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। सिंह के मुताबिक, सनातन धर्म हजारों साल पुराना है, जबकि हिंदुत्व शब्द सावरकर ने दिया था। सनातन धर्म में कटुता और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने संविधान पर खतरे और नागरिकता के अधिकार पर सवाल उठाए। सिंह ने कहा कि संविधान हर नागरिक को मतदान का अधिकार देता है। मतदाता सूची में नाम जोड़ना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, न कि यह तय करना कि कौन भारत का नागरिक है।

दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए। सिंह ने कहा कि नोट चोरी और वोट चोरी, दोनों मामलों में ज्ञानेश कुमार की भूमिका है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस, विहिप और बजरंग दल पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी संगठन कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। ये संगठनों पर नफरत फैलाने और कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले संगठन हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या इसी कट्टरता के कारण हुई थी, उन्होंने नाथूराम गोडसे को आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति बोला। सनातन धर्म और हिंदू धर्म के संबंध को लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी। ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर भी दिग्विजय सिंह ने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता प्रभावित करने के आरोप लगाए। पूर्व सीएम ने वोट चोरी और नोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की पैरवी की।

वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 100वें स्थान पर

भारत में 10 प्रतिशत कुपोषित, 29 प्रतिशत बौने बच्चे

नई दिल्ली । बढ़ती अर्थव्यवस्था का दंभ भरने वाले भारत की भूखमरी के मामले में बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का 122 देशों में 100वां स्थान है। 2012 के बाद से ही भारत भुखमरी की गंभीर श्रेणी में है और इससे बाहर निकलने के लगातार प्रयास कर रहा है। वर्ष 2018 से 2026 में भारत की गरीबी 25.8 से घटकर 24.1 हुई है। हालांकि इसमें केवल 1.7 अंकों का सुधार हुआ है, जबकि इसके मुकाबले कांग्रेस सरकार के शासनकाल में 2006 से 2012 के बीच 8.2 अंकों का सुधार हुआ था।



आज भी भारत की 9.8 फीसदी आबादी कुपोषित है और 29.3 प्रतिशत बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से कम लंबाई के हैं, अर्थात बौनेपन के शिकार हैं। भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दुबलापन बढ़कर 19% हो गया है, जो दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है। दक्षिण एशिया का सूचकांक स्कोर 23.5 है और इस क्षेत्र में बच्चों के दुबलेपन की दर 15.8 प्रतिशत है, जो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में सबसे अधिक है। वर्ष 2018 के बाद से 31 देशों में गरीबी बढ़ी है, वहीं अफ्रीका में युगांडा और टोगो ने सुधार किया है, जबकि दक्षिण एशिया में वर्ष 2000 के बाद नेपाल ने सबसे अधिक सुधार हासिल किया है।

मोदी के शासनकाल में नहीं हुआ गरीबी में सुधार

भारत में भूख कम करने की दिशा में प्रगति धीमी पड़ गई है। साल 2018 से 2026 के बीच भारत की गरीबी के अंक 25.8 से घटकर 24.1 ही हो पाए, यानी इसमें केवल 1.7 अंकों का सुधार हुआ है, जबकि इसके मुकाबले कांग्रेस के शासनकाल में 2006 से 2012 के बीच गरीबी में 8.2 अंकों का सुधार हुआ था।

मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आज आएगा फैसला...

कोर्ट में पेश हो सकते हैं कांग्रेस नेता

सुल्तानपुर । सुल्तानपुर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में कथित अपमानजनक बात कहने के आरोप में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर मानहानि का केस चल रहा है। इस केस में सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। 13 अक्टूबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थीं। इसके बाद जज ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाने की तारीख तय की थी।

उत्तर प्रदेश की एक विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट इस मामले में 26 अक्टूबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। और अदालत ने राहुल को खुद कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। भाजपा के नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल के खिलाफ अदालत में एक मानहानि का केस दर्ज करवाया था। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने साल 2018 में ही बेंगलुरु शहर के भीतर एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह के खिलाफ कुछ बेहद आपत्तिजनक और विवादित बातें कही थीं।

महेश्वर के घाट पर मिले इंदौर के 343 वोटर कार्ड

डिजिटल कार्ड पर 2016 का साल दर्ज होने का दावा...

महेश्वर । खरगोन जिले के महेश्वर में इंदौर के 343 वोटर कार्ड मिले हैं। रविवार दोपहर सफाई अभियान से जुड़ी संस्था के सदस्यों को ये कार्ड नर्मदा नदी में तैरते और किनारे पड़े मिले। कार्ड पर इंदौर के तिलक नगर, आस्था पैलेस सहित अन्य पते दर्ज हैं। इंदौर से करीब 90 किलोमीटर दूर इतनी बड़ी संख्या में कार्ड मिलने के बाद कांग्रेस ने देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ वोट चोरी की एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक घंटे तक धरना दिया।



खरगोन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाईक का दावा है कि कार्डों पर 2016 का साल दर्ज है, जबकि ये डिजिटल कार्ड हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर डिजिटल कार्ड की शुरुआत 2021 में हुई तो इन पर 2016 कैसे दर्ज है। उन्होंने कहा कि वोटर आईडी के एपिक नंबर को सिस्टम में डालकर कार्डों की स्थिति पता की जा सकती है।

धधक रहा है फ्रांस, महंगाई और स्कूलों के बजट में कटौती के विरोध में सड़कों पर 4 लाख प्रदर्शनकारी

1000 गिरफ्तार- दबाव में मैक्रों सरकार

पेरिस । फ्रांस में महंगाई और स्कूलों के लिए कम बजट मिलने के विरोध में देशभर में करीब 4 लाख 10 हजार लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। गृह मंत्रालय के मुताबिक, राजधानी पेरिस में ही करीब 1 लाख 10 हजार लोग सड़कों पर उतरे।



यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ, जब एक हफ्ते पहले ही फ्रांस के कई शहरों में हिंसा, तोड़फोड़ और लूटपाट की घटनाएं हुई थीं। लगातार हो रहे प्रदर्शनों से राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने बताया कि प्रदर्शनों के दौरान करीब 1,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस की काले कपड़े पहने कुछ लोगों के समूहों से गंभीर झड़पें हुईं।

मैक्रों सरकार के सामने बड़ी चुनौती

फ्रांस में मई 2027 में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में लगातार हो रहे प्रदर्शन मैक्रों सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि प्रदर्शनकारियों को शहरों के मुख्य इलाकों और दुकानों व कारोबार वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाए। हिंसा रोकने के लिए पेरिस और कई दूसरे शहरों के कुछ इलाकों में सीमित समय के लिए कर्फ्यू भी लगाया गया है। मैक्रों ने अधिकारियों से उन प्रदर्शनों पर रोक लगाने को भी कहा है, जो ट्रेड यूनियनों से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने ऐसे प्रदर्शनों को अवैध बताया।

जस्टिस कौल की किताब पर सियासी भूचाल...

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की किताब के खुलासों के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाया है। किताब में जजों की नियुक्तियों में सरकारी दखल, पूर्व सीजेआई के रवैये और संवेदनशील मामलों में पीठ बदलने जैसे संगीन मुद्दे उठाए गए हैं।

कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका का दबावमुक्त होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल की आने वाली किताब के अप्रकाशन संस्करण रुकने के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं।

बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान

28 अक्टूबर को आंध्र तट से टकराएगा, तमिलनाडु-पुडुचेरी में तेज बारिश, ओडिशा के 5 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद

कोलकाता । बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया रविवार को चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसे अनंब नाम दिया गया है। इसके असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, चक्रवाती तूफान 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है।

इस दौरान हवा की रफ्तार 115 से 125 किमी प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में 26 से 29 अक्टूबर तक भारी बारिश का अनुमान है। ओडिशा के गंजाम, गजपति, रायगढ़ा, कोरापुट और मलकानगिरी जिले में 28 और 29 अक्टूबर को सभी स्कूल-कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश दिए गए हैं। पुडुचेरी में शनिवार रात से लगातार बारिश हो रही है। वहीं, तमिलनाडु में भारी बारिश के बीच इरोड जिले में रविवार को कोडिवेरी बांध पर लगातार दूसरे दिन पर्यटकों की एंट्री बंद रही। केरल में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में रेड अलर्ट है।

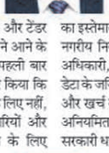
सरकारी खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने सरकार का सख्त रुख

जेम पोर्टल पर गड़बड़ी करने वाले 392 अधिकारियों पर गाज...

● भोपाल

मध्य प्रदेश में सरकारी खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल के जरिए की गई खरीदी में भारी वित्तीय गड़बड़ी और नियमों को ताक पर रखने के मामलों में सरकार ने लगभग 392 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई की जद में करीब 135 मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) भी आए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे ने स्पष्ट किया है कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता के गाढ़े पसीने की कमाई का पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करना और उसका पूरा लाभ नागरिकों तक पहुंचाना है। गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए अब तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

दरअसल, नगरीय निकायों में खरीदी और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों से जुड़े वीडियो सामने आने के बाद अपर मुख्य सचिव संजय दुबे ने पहली बार मामले पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो अनियमितताओं को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों और विभाग की निगरानी व्यवस्था समझाने के लिए आयोजित प्रशिक्षण सत्र (16 अप्रैल 2026) का हिस्सा था। दुबे के मुताबिक, विभाग ने खरीदी और भुगतान में गड़बड़ियां पहचानने के लिए ई-नगरपालिका सॉफ्टवेयर, जेम पोर्टल के आंकड़ों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। दुबे ने बताया कि प्रशिक्षण में नगरीय निकायों के कमिश्नर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सब इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को डेटा के जरिए समझाया गया कि विभाग उनकी खरीदी और खर्च की निगरानी कैसे करता है। इसका उद्देश्य अनियमित भुगतान, नियमों से ज्यादा खर्च और सरकारी धन का दुरुपयोग रोकना था।



निगरानी के लिए तकनीक और एआई का इस्तेमाल

राज्य सरकार वित्तीय अनियमितताओं पर नजर रखने और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल कर रही है। सरकार का उद्देश्य सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना और योजनाओं का लाभ वास्तविक हितग्राहियों तक पहुंचाना है। सरकार का कहना है कि जनता के पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने और वित्तीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी और कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगी।

संपादकीय

संविधान पीठ के इंतजार में न्याय!

सुप्रीम कोर्ट में लंबित 25 प्रकरण न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल

न्यायपालिका का अस्तित्व केवल फैसले सुनाने से नहीं, बल्कि समय पर न्याय देने से कायम रहता है। जब न्याय के सर्वोच्च मंदिर सुप्रीम कोर्ट में ही महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों पर वर्षों तक सुनवाई नहीं होती, फैसले सुरक्षित रखकर लंबे समय तक फैसले सुनाए नहीं जाते हैं, याचिकाकर्ता तारीखों के इंतजार में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, तब सवाल केवल न्याय में देरी का नहीं, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की जवाबदेही का खड़ा होता है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के गठन और सुनवाई के इंतजार में लगभग 25 महत्वपूर्ण प्रकरण लंबित होने की जानकारी न्यायिक व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाती है। इनमें कुछ मामले 16 वर्षों से संविधान पीठ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि छह मामलों में सुनवाई पूरी होने के बाद भी कथित तौर पर एक दशक से फैसले लंबित हैं। जिन न्यायाधीशों ने इन मामलों की सुनवाई की, उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आखिर जिन मामलों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई योग्य और महत्वपूर्ण माना, वे वर्षों तक निर्णय की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? इन प्रकरणों का प्रभाव किसी एक याचिकाकर्ता तक सीमित नहीं है। आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, रोजगार, केंद्र और राज्यों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, महिला संपत्ति अधिकार तथा डिजिटल निजता करोड़ों नागरिकों के संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों एवं उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। देशद्रोह कानून, विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार और न्यायाधिकरणों के सदस्यों की सेवा शर्तों से संबंधित मामलों में भी लंबित सुनवाई संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। जब कानून की व्याख्या ही सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो, तब सरकारों, प्रशासन, नागरिकों और निचली अदालतों के सामने अनिश्चितता बनी रहती है। इससे अराजकता की स्थिति बनती है। सबसे गंभीर प्रश्न यह है, न्यायपालिका अपनी प्राथमिकताएं कैसे तय कर रही है?

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर का अधिकार प्राप्त है। न्यायालय के पास उपलब्ध न्यायाधीशों, पीठों और न्यायिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करके संवैधानिक मामलों की सुनवाई के लिए निश्चित समय-सारणी बनाई जा सकती है। संविधान पीठ के मामलों को वर्षों तक लंबित छोड़ना, किसी भी स्थिति में सामान्य न्यायिक प्रक्रिया मानकर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। विशेषकर उन मामलों में, जिनका निर्णय पूरे देश की कानूनी व्यवस्था को दिशा देने वाला हो। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को लेकर आम नागरिकों के बीच एक चिंताजनक धारणा बनने लगी है। जिन मामलों में सरकार पक्षकार होती है, उनमें सुनवाई और निर्णय की प्रक्रिया असाधारण रूप से लंबी खिंच जाती है, कहीं अंतरिम आदेशों के सहारे परिस्थितियां बदल जाती हैं। चुनाव आयोग, और एसआईआर मामले में लंबी सुनवाई के बाद टुकड़े-टुकड़े में फैसला देने और जिन प्रक्रियाओं को लेकर लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, उस पर निर्णय अभी तक लंबित है। कहीं फैसला सुरक्षित रखने के बाद महीनों और वर्षों तक निर्णय नहीं आता, कहीं महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों का अंतिम समाधान किए बिना मामला अधीनस्थ अदालत में भेज दिया जाता है। यह धारणा सही है या गलत, इसकी निष्पक्ष समीक्षा स्वयं न्यायपालिका को करनी चाहिए। न्यायपालिका की विश्वसनीयता केवल इस बात से नहीं बचेगी, वह अपनी निष्पक्षता का दावा करे। सुप्रीम कोर्ट के जज भगवान भी नहीं हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के दिए गए फैसले और कार्यों की न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। फैसलों और कार्यप्रणाली में निष्पक्षता स्पष्ट रूप से दिखनी भी चाहिए, उसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। सरकार के विरुद्ध याचिका दायर करने वाला नागरिक पहले ही सत्ता और संसाधनों के असमान मुकाबले में खड़ा होता है। 70 फीसदी मामलों में सरकार के खिलाफ मामले अदालत में जाते हैं। सरकारों के पास असीमित शक्ति होती है। याचिकाकर्ता अधिकांश मामलों में निर्बल होता है। उसको कानून और अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसी दयनीय स्थिति में उसे वर्षों तक न्यायालय के दरवाजे पर न्याय का इंतजार करना पड़े, तो उसके कानूनी अधिकार का महत्व ही समाप्त हो जाता है। चुनावी विवादों में कार्यकाल पूरे हो जाते हैं, नीतियों के प्रभाव स्थायी हो जाते हैं, नागरिकों के अधिकार प्रभावित होते हैं, अंतिम फैसला नहीं आता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद भी जब उसे न्याय नहीं मिलता है, ऐसी स्थिति में न्याय पर भरोसा कमजोर पड़ जाता है। समान आदमी न्याय पाने के लिए नेताओं और अपराधियों के दरवाजे खटखटाने लगता है।

संविधान पीठ के निर्णय पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए नजीर बनते हैं। इसलिए इनके लिए समयबद्ध सुनवाई, फैसले सुनाने की स्पष्ट समय-सीमा और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा आवश्यक है। जिन मामलों में फैसला सुरक्षित है, उनकी स्थिति भी सार्वजनिक और जवाबदेह होनी चाहिए। न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार हो या नागरिक, दोनों पक्षों को अनिश्चितकालीन न्यायिक देरी का लाभ न मिले। यह तभी हो सकता है, जब समय पर न्याय हो। न्याय में देरी केवल प्रशासनिक कमजोरी नहीं, लोकतंत्र के प्रति नागरिकों के विश्वास का आधार भी है। यदि सर्वोच्च न्यायालय में ही न्याय की प्रतीक्षा वर्षों तक जारी रहती है, तो आम आदमी किससे समय पर न्याय की उम्मीद करेगा? न्यायपालिका की गरिमा उसके अधिकारों और शक्तियों से नहीं, बल्कि नागरिकों को समय पर मिलने वाले न्याय से स्थापित होती है। न्याय यदि समय पर नहीं मिलता, तो संविधान में दिए गए अधिकार कागजों तक सीमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। भारत में विक्रमादित्य की न्याय की बड़ी प्रशंसा होती है। पंचायत के न्याय को भी प्राइमरी शिक्षा में पढ़ाया जाता है। अब आवश्यकता तारीख पर तारीख की परंपरा को तोड़ने और न्याय को निश्चित समय सीमा में बिना किसी दबाव या किसी से प्रभावित हुए बिना न्यायक दृष्टि से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, वर्तमान समय में यह नहीं हुआ तो कभी भी विस्फोटक स्थिति बन सकती है। जब लोग न्यायपालिका पर ही विश्वास नहीं करेंगे।

संविधान सर्वोपरि : मूल अधिकारों में छेड़छाड़ नहीं कर सकती संसद!

मौलिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता, मताधिकार, संवैधानिक संस्थाओं की शक्ति पर संसद के अधिकार सीमित



लोकेन्द्र जैन



भारतीय संविधान केवल शासन चलाने का दस्तावेज नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षक है। संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार अवश्य है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। संसद के दोनों सदन मिलकर भी संविधान के मूल ढांचे की समाप्त नहीं कर सकते। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक शक्ति है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई, जिसमें संसद, सरकार और न्यायपालिका सभी संविधान के अधीन अपने कर्तव्यों और अधिकारों का पालन करें। संसद कानून बना सकती है, सरकार उनका क्रियान्वयन कर सकती है, न्यायपालिका को समीक्षा का अधिकार दिया गया। किसी को भी संविधान की मूल भावना को कम या नष्ट करने का अधिकार नहीं है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों भगवानों के पास अलग-अलग दायित्व हैं। संविधान निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए इन्हीं तीन शक्तियों को विधायक का कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में स्वीकार किया जनता जनार्दन अपनी मर्जी से सरकार चुनेगी, चुने हुए प्रतिनिधि जनता की इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे।यह भारतीय संविधान की मूल भावना है। संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को ही राजा माना गया है।

संसद की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक मुहर: 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 7:6 के बहुमत से स्पष्ट किया। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ और उसे समाप्त नहीं कर सकती है। इस फैसले ने संसद की संशोधन शक्ति की संवैधानिक सीमा निर्धारित कर दी है। लोकतंत्र, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जैसी विशेषताएं संविधान के मूल ढांचे से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ है कि संसद अपने बहुमत के बल पर ऐसी व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती, जिसमें नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए। इस मामले में विधायिका और कार्यपालिका के अधिका भी सीमित हैं।

मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: भारतीय संविधान के भाग तीन में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 19 नागरिक स्वतंत्रताओं, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को बनाया गया। उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट के माध्यम से अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है। जो विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका की नियंत्रण शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं है, मौलिक अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं हो सकता है। संसद संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार संशोधन कर सकती है। लेकिन ऐसे सभी संशोधन न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। संविधान के मूल ढांचे में संसद भी छेड़छाड़ नष्ट नहीं कर सकती है।

आपातकाल ने सिखाया संवैधानिक सीमाओं का महत्व: 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रताओं और न्यायिक समीक्षा पर गंभीर सवाल उठे। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने संसद की संशोधन शक्ति को व्यापक बनाने और न्यायिक समीक्षा को सीमित करने के प्रयास किए थे। 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमे संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने और न्यायिक समीक्षा को समाप्त करने का प्रयास किया था। अदालत ने स्पष्ट किया, सीमित संशोधन शक्ति स्वयं संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।

मतदान का अधिकार, लोकतंत्र और संविधान की असली ताकत: मतदान भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। अनुच्छेद 326 मे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में वयस्क मताधिकार का संवैधानिक आधार प्रदान करता है। मतदान के अधिकार की कानूनी प्रकृति मौलिक अधिकारों से अलग है। इसे संविधान और चुनाव संबंधी कानूनों के प्रावधानों के अनुसार समझना आवश्यक है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नागरिक के मूल अधिकार तथा लोकतांत्रिक शासन संविधान के मूल ढांचे के महत्वपूर्ण अंग हैं। इसलिए संसद या सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकती, जो लोकतंत्र की बुनियादी अधिकारों को नष्ट या सीमित कर सके। संसद को संविधान से शक्ति प्राप्त होती है। संविधान संसद ने नहीं बनाया। विधायिका को बहुमत के आधार पर सरकार बनाने का अधिकार मिलता है। संविधान की मूल भावना को समाप्त करने का अधिकार संसद के पास नहीं है। भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती इसी में है, जिसमे नागरिकों के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्ष चुनाव सरकार की इच्छा पर नहीं, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं और परंपराओं पर आधारित हों।

न्यायपालिका की समक्षा के अंतर्गत संवैधानिक संस्थाएं : भारत में सभी संवैधानिक संस्थाएं जिन्हें संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, वह सभी न्यायपालिका की समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। चुनाव आयोग भी न्यायपालिका की समीक्षा के अंतर्गत है। चुनाव आयोग को ऐसे कोई अधिकार संविधान से नहीं मिले, जिससे वह अपनी मनमानी कर सके। चुनाव आयोग को भी नियमों के अंतर्गत काम करना होगा। चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर प्राप्त हों, सभी नागरिक अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर पायें। इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है, वह भी जवाबदेह है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और चुनाव आयोग पर सरकार की दखलंदाजी बढ़ी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से दूरी बनाई। चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में वह निष्पक्षता देखने को नहीं मिली। जो इसके पहले चुनाव आयोग में देखने को मिलती थी। मतदाता सूचियों को लेकर भी जिस तरह के बदलाव किए गए। बीएलओ और ईआरओ के अधिकार चुनाव आयोग ने सीमित कर दिये चुनाव व्यवस्था का केंद्रीयकरण करते हुए चुनाव परिणाम भी केंद्रीकृत व्यवस्था से किए जाने लगे, जिसके कारण देश भर में मुख्य चुनाव आयुक्त जानेश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देश में पहली बार चुनाव आयोग के प्रति इतना अविश्वास देखने को मिल रहा है।

देश भर में आंदोलन चल रहे हैं। स्वतंत्रता की बात से अभी तक के इतिहास में पहली बार 13 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। नागरिकों के अधिकार को चुनाव आयोग द्वारा चुनौती दी गई है। ऐसा करने का उसके पास कोई अधिकार भी नहीं था। ऐसी स्थिति में सभी संवैधानिक संस्थाओं को समझना होगा, उनके अधिकार और जिम्मेदारी दोनों ही समीक्षा के अधिकार और जवाबदेही से अलग नहीं हैं। कोई भी संस्था संविधान से मिले अधिकारों का दुरुपयोग या मनमानी नहीं कर सकती है।

जत हटके

अब दिमाग में उठ रहे सवाल को समझ सकेंगे?

चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक तैयार की है, जो इंसान के दिमाग में उठ रहे सवाल रुपी रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा दिमाग मॉनिटर बनाया है, जिसे पहना भी जा सकता है क्योंकि इसका वजन सिर्फ एक ग्राम है। इस वायरलेस डिवाइस का नाम 'एयरस्कोप' है। इसे चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी और चीनी पीएलए मेडिकल स्कूल के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है। इससे जुड़ा रिसर्च साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस माइक्रो मिनी डिवाइस के जरिये दिमाग की हर गतिविधि को न सिर्फ देखा जा सकेगा बल्कि उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकेगा।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयरस्कोप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब इसकी टेस्टिंग हुई तो यह एक ही समय में चूहे के दिमाग की 8500 से ज्यादा तंत्रिका कोशिकाओं यानी न्यूरॉन्स की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकता है। न्यूरॉन्स वे कोशिकाएं हैं, जो दिमाग में सूचनाओं का आदान-प्रदान करती हैं। पहले इस तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए जानवरों का सिर स्थिर रखना पड़ता था या उन्हें तारों से जुड़े उपकरणों के साथ देखा जा सकता था, ऐसे में ये मुश्किल होता था कि उनके नेचुरल मूवमेंट को समझा जा सके। अब एयरस्कोप की मदद से ये काम आसान हुआ है। एक ग्राम वजन होने की वजह से यह उपकरण हर वक्त पहना जा सकता है। यह डिवाइस वैज्ञानिकों को डिप्रेशन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े दिमाग की गतिविधियों में बदलाव को समझने में मदद कर सकती है, जिससे भविष्य में बेहतर उपचार विकसित करने के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह जानवरों के आपसी व्यवहार, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक संबंधों के दौरान न्यूरॉन्स कैसे सक्रिय होते हैं, इसका ज्यादा बारीकी से अध्ययन करने में भी सहायक होगी। ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस और कैंसर एवं प्रतिरक्षा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भी इसके विकासकर्ता भविष्य में इसके उपयोग की संभावना देखते हैं।

फोटो ऑफ द डे



टोरंटो में हाउलोवीन बैटले नाम की स्पर्धा में अपने कुत्तों के साथ भाग लेते हुए उनके मालिक। ये स्पर्धा इनके कॉस्ट्यूम की होती है।

सुविचार

चतुराई और चालबाजी दो चीजें हैं, एक में ईश्वर की प्रेरणा होती है और दूसरा हमारी फितरत से पैदा होता है।

- सुमन सिन्हा

जो शिक्षा मनुष्य को संकीर्ण और स्वार्थी बना देती है, उसका मूल्य किसी युग में चाहे जो रहा हो, अब नहीं है।

- शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय

प्रसंगत

पश्चात्ताप

कर्णवास का एक पंडित महर्षि दयानंद सरस्वती को प्रतिदिन गालियाँ क देता करता था, पर महर्षि शांत भाव से उन्हें सुनते रहते और उसे कुछ भी उत्तर न देते। एक दिन जब वह गाली देने नहीं आया तब महर्षि ने लोगों से उसके न आने का कारण पूछा। लोगों ने बताया, 'वह बीमार है।' महर्षि फल और औषध लेकर उसके घर पहुँचे। वह महर्षि को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और अपने असद व्यवहार के लिए क्षमा माँगने लगा। इसके बाद उसका गाली देना सदा के लिए छूट गया।

व्यंग

लॉ एंड ऑर्डर

महेशचंद्र द्विवेदी

प्रेसवाले ने एक पुलिस अधिकारी से पूछा, 'क्या ला ऐंड आर्डर दुरुस्त है?'

पुलिसवाला झिझका, फिर बोला, 'हाँ, फिफ्टी फिफ्टी।' प्रेसवाले ने प्रतिप्रश्न किया, 'क्या मतलब?'

पुलिसमैन ने प्रत्युत्तर दिया, 'ला सुस्त है, आर्डर चुस्त है।' प्रेसवाला चकित हो बोला, 'दोनों शब्द तो बोले जाते एकमुश्त हैं?' पुलिसवाला उसको नादान समझकर मुस्कया, फिर समझाया, 'हाँ, अंग्रेजी जमाने में एकमुश्त थे - अब आजादी है, सो एक दूसरे से आजाद हो गए हैं।' प्रेसवाला स्पष्ट अर्थ न समझा, फिर प्रश्न किया, 'तो भी एक सुस्त और एक चुस्त कैसे?' पुलिसवाले ने व्याख्या दी, 'देश के नेताओं ने लॉ को अफ़ीम की लत लगा दी है - दिन रात खुमार में सोता है और जब जागता है तो लड़खड़ाते हुए चलता है। पर उन्होंने अपने आर्डर को सुपारी लेने जैसा बना दिया है, ''इधर सुपारी लो, उधर करो गर्दन खलास,नहीं तो मत रखो कमाऊ पोस्टिंग की आस' प्रेसवाले को लगा कि इस पर तो लंबी स्टोरी बन सकती है, इसलिए झिझोड़ने के अंदाज में बोला, 'बात साफ़ नहीं हुई, जरा गुढ़ार्थ समझाइए।' पुलिसवाला 'लुप्तप्राय' प्रजाति का संवेदनशील पुलिसमैन था, फूट पड़ा, 'लगता है आप ने किसी कारसाज दरोगा का इंटरव्यू नहीं लिया है, जो किसी को पकड़ते समय उससे कहता है कि पकड़ने हेतु ला की धारा तो हम फुर्सत में देखते हैं जब आदमी को सींखचों के अंदर डाल चुके होते हैं। आपका किसी सफल वकील से साबका नहीं पड़ा है, जो कहते हैं कि ला पढ़ने का क्या फ़ायदा, जब काम दलाली से ही होना है? आपने किसी अहलमद से डील नहीं किया है, जो कहता है कि खुश कर देने पर मैं अपराधियों की फ़ाइल तब तक गर्द में दबा सकता हूँ जब तक मु ई और गवाह दोनो अल्लाह के प्यारे न हो जाएँ?''

''हाँ, आर्डर आर्डर है - उसका पालन तो होना ही है, चाहे कुसुम-सा कल्याणमय हो,
या मायामय सखुत हो,
या फिर शिवमय मुलायम हो।''

हममें से अधिकतर जनसेवक आर्डर के पालन में लेशमात्र कोताही नहीं करते हैं -आप बताएँ उस अधिकारी का नाम जिसने कालिदास-मार्ग पर प्रायः दिखाई पड़ने वाले कुसुम की राय को पूजा के पुष्प-सम सिरमाथे न लगाया हो और कल्याण-कोष की वृद्धि में अपना नाम न दर्ज कराया हो? सोचें कि सरकारी धन से बर्थडे मनाने और करोड़ों की बर्थडे गिफ्ट जुटाने के आदेश के पालन मे कौन-सा प्रशासक जी-जान से नहीं जुटा था? था ऐसा कोई अधिकारी जिसने आंबेडकर पार्कों के नाम पर ग़रीबों के खून-पसीने की कमाई से सींचित राजकोष को उलीचने में कोताही की हो? और अकूत कमीशन खाया और खिलाया न हो? कितने थे पुलिस अधिकारी जिन्होंने सत्तर दिन में सत्तर प्रतिशत अपराध घटा देने के मायावी आदेश का पालन अपराधों के लिखे जाने पर रोक लगाकर न किया हो?बताइए उस अधिकारी का नाम जिसने गत चुनाव में सत्तादल को जिताने के प्रयत्न में छिलाई कर शासनादेश का उल्लंघन किया हो? या फिर शासनसंदेश के निष्ठापूर्वक अनुपालन में गुंडों को बूथ-कैप्चरिंग कराने में मदद न की हो? आदेश होने पर आजकल कौन पुलिस अधिकारी निर्देाष को बख्शता है या अपराधी को पकड़ता है?

चिंतन-मनन

क्यों कहते हैं विष्णु भगवान को नारायण

भगवान विष्णु के हजारों नाम हैं। इनमें एक प्रमुख नाम है नारायण। फिल्मों, टीवी सीरियल या रामलीला में आपने देखा होगा कि नारद मुनि भगवान विष्णु को नारायण नाम से पुकारते हैं। इस नाम का धार्मिक रूप से बड़ा महत्व है। इस एक नाम में सृष्टि का संपूर्ण सार छिपा हुआ है। इसलिए शास्त्रों में अधिकांश स्थानों पर विष्णु भगवान को नारायण नाम से संबोधित किया गया है। हिन्दू धर्म में अठारह पुराणों का वर्णन मिलता है। इन अठारह पुराणों में विष्णु पुराण एक है। इस पुराण में सृष्टि की रचना का वर्णन किया गया है। इसी प्रम में बताया गया है कि सप्तकार विष्णु भगवान ने वाराह रूप धारण करके पृथ्वी को रसातल यानी पाताल लोक से उठाकर जल के मध्य में स्थित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्व, रज और तम गुणों से असुर, देव, राक्षस, यक्ष, मनुष्य, सर्प एवं अन्य जीव-जन्तुओं की रचना की। विष्णु पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के समाप्ति के समय सब कुछ जल में समा जाता है और संपूर्ण ब्रह्माण्ड अंधकारमय हो जाता है।

स्वास्थ्य

बच्चों के लिए इस प्रकार बनाये माउथ-फ्रेशनर

अगर आज मानते हैं कि माउथ फ्रेशनर की आवश्यकता केवल बड़ों को होती है तो अपना विचार बदल दें। इसका कारण है कि बच्चों के भी दांत खराब हो सकते हैं इसलिए हमारी तरह ही छोटे बच्चों को भी माउथ फ्रेशनर की आवश्यकता होती है पर बाजार में बिकने वाले माउथ फ्रेशनर उनके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत अधिक मात्रा में रसायन होते हैं।

ऐसे में उनके लिए एक ऐसा माउथ फ्रेशनर होना चाहिए जो पूरी तरह प्राकृतिक हो और स्वाद में भी कड़वा न हो। आप चाहें तो अपने बच्चों के लिए घर पर ही माउथ फ्रेशनर तैयार कर सकती हैं। अनार के छिलकों का इस्तेमाल करके माउथ फ्रेशनर बनाया जा सकता है। ये माउथ फ्रेशनर न केवल बच्चों के लिए फायदेमंद रहेगा बल्कि इसे बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार के छिलके में एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो ओरल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अनार के छिलके से तैयार माउथ फ्रेशनर मुंह के अल्सर और मुंह की दुर्गंध को दूर करने का काम करता है। अनार का एंटी-माइक्रोबायल एक्टिविटी स्ट्रेप्टोकोक्स म्यूटेन बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है. कैसे तैयार करें अनार के छिलके का माउथ फ्रेशनर? अनार को काटकर उसके दानों को सफाई से निकाल लें. अनार के छिलके को धूप में सूखने के लिए रख दें।

जब छिलके पूरी तरह सूख जाएं तो उन्हें पीसकर पाउडर तैयार कर लें। एक गिलास पानी में एक चम्मच इस पाउडर को मिलाकर उबालें। इसे ठंडा होने दें। जब ये घोल ठंडा हो जाए तो इस छान लें। इस तरल को किसी जार या शीशी में भरकर रख दें। आपका माउथ फ्रेशनर तैयार है. बच्चा जब भी कुछ खाए तो उसे माउथ फ्रेशनर से मुंह साफ करने की आदत डालें।

राज काज

हरदीप पुरी का जाना तय

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का जाना तय हो गया है। उनका पुण्य काल समाप्त हो गया है। अब पाप कर्मों का उदय शुरू हो चुका है। पहले उन्हें राज्यसभा की टिकट नहीं दी गई। यह पहला झटका था। अब एप्सटीन फाइल में उनका फोटो यौन अपराधी जैफ्री एपस्टीन और उसका फोटो वायरल हुआ है। फिरभी वह आमने-सामने बैठकर बात कर रहे हैं। इसके बाद अब उनका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए अब वह कोई काम के नहीं रहे। आगे उनकी कोई सदस्य भी नहीं होगी। उनका भविष्य अब अंधकारमय हो चला है। सत्य कभी एकता नहीं रहता है। हरदीपपुरी को अब समझ में आ रहा है।

कर्नाटक में रिटेंग ऑपरेशन की बाढ़

कर्नाटक में रिटेंग ऑपरेशन इन दिनों बड़ी चर्चाओं में है. पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सिद्धरमैया, वीडियो में एक महिला के साथ दिख रहे हैं. उनके चरित्र हनन का प्रयास इस रिटेंग ऑपरेशन ने किया गया है, वहीं एक डायरी भी चर्चाओं में है. यह डायरी वर्तमान मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की है. जिसमें डायरी के कई पन्ने ईडी के छापे के बाद निकलकर सामने आए हैं. एक रिटेंग ऑपरेशन में पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदुरप्पा भी चर्चाओं में आ गए हैं. कर्नाटक में नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है. यह रिटेंग ऑपरेशन कर कौन रहा है।

महाराष्ट्र के स्वाद में इंदौरी तड़का, जत्रा में उमड़ा जनसैलाब

इंदौर।

सर्व मराठी भाषी सोशल एंड कल्चरल सोसायटी द्वारा आयोजित तीन दिवसीय मेगा इवेंट 'जत्रा - मराठी वारसा फेस्टिवल' का दूसरा दिन उत्साह, सांस्कृतिक रंगों और पारंपरिक मराठी व्यंजनों के नाम रहा। शनिवार को शाम ढलने से पहले ही आयोजन स्थल पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। शाम होते-होते जत्रा परिसर में रौनक बढ़ती गई और रात आठ बजे तक पूरा ग्राउंड लोगों से गुलजार हो उठा।







23 से 25 अक्टूबर तक आयोजित इस फेस्टिवल में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लोगों के लिए प्रवेश और विभिन्न गतिविधियां रखी गई हैं। महाराष्ट्र की पारंपरिक संस्कृति और व्यंजनों के साथ इंदौरी अंदाज का अनूठा संगम शहरवासियों को खूब आकर्षित कर रहा है।

जत्रा में पहुंचे लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लेने के साथ ही महाराष्ट्र के लजीज व्यंजनों का जमकर स्वाद लिया। खाने-पीने के स्टॉल देर रात तक गुलजार रहे और हर ओर लोगों की चहल-पहल दिखाई दी। पारंपरिक मराठी वेशभूषा, लोककलाओं, संगीत और खानपान ने आयोजन को एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव का रूप दे दिया।

जत्रा ने दोगुना किया लोगों का उत्साह

आयोजन समिति की अध्यक्ष एवं सर्व मराठी भाषी सोशल एंड कल्चरल सोसायटी की अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद ने बताया कि जत्रा के दूसरे दिन भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। दोपहर 2 बजे से ही आयोजन स्थल पर लोगों का आना शुरू हो गया था और शाम होते-होते बड़ी संख्या में परिवार यहां पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि लोगों की भागीदारी और मराठी संस्कृति के प्रति उनका प्रेम देखकर मन प्रफुल्लित हो गया। जत्रा का उद्देश्य मराठी विरासत, परंपराओं, लोककलाओं और खानपान को एक साझा मंच पर प्रस्तुत करना है, जिसे लोगों का भरपूर प्रतिसाद मिल रहा है।

पुणे और मुंबई से भी जत्रा देखने पहुंचे मेहमान

इंदौर के विजय नगर क्षेत्र स्थित गुजराती स्कूल में आयोजित जत्रा मराठी वारसा फेस्टिवल में पुणे और मुंबई से आए मेहमानों ने भी शिरकत की। इंदौर आए ये परिवार शहर में आयोजित इस बड़े मराठी सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बनने पहुंचे। उनके लिए यह देखना खास रहा कि महाराष्ट्र से दूर इंदौर में भी मराठी समाज अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं को सहेजने के साथ अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जत्रा ने स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से आए मेहमानों को भी मराठी विरासत से रूबरू होने का अवसर दिया।

लावणी, गोंधल और पोवाड़े ने बांधा समां

महाराष्ट्र से आए लोकनृत्य कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद लावणी, गोंधल और पोवाड़े की प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को महाराष्ट्र की लोकसंस्कृति के रंग में रंग दिया। लगभग चार घंटे तक चले इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए शाम 7 बजे से ही दर्शक अपनी-अपनी जगह पर बैठ गए थे। कलाकारों की लय, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा। विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरवशाली इतिहास और मराठी लोकपरंपरा से जुड़े पोवाड़ों ने कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा। जत्रा में लावणी के लिए %महाराष्ट्रचे मानकारी% नाम की कलाकारों की टीम महाराष्ट्र से इंदौर आयी हुई है।

ठेठ मराठी और गावठी व्यंजनों का लिया स्वाद

जत्रा का फूड सेक्शन भी लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा। यहां महाराष्ट्र के पारंपरिक और ग्रामीण स्वादों से लेकर लोकप्रिय मुंबई स्ट्रीट फूड तक की विस्तृत श्रृंखला देखने को मिली। झुणका-भाकर, भरली वांगी, ठेसा-भाकर, बासुंदी, आप्पे, साबूदाना वड़ा, पुरणपोली, वड़ा पाव, मिसळ पाव, धपाटे, भरीत-भाकरी, श्रीखंड-पुरी, अनारसे, चकली, भाकरवड़ी, मुंबई की स्पेशल भेल, कोथिंबीर वड़ी, सांबरवड़ी, वाटली दाल, घिरड़े (चिले), मसाला भात, कढ़ी गोळा, कलाकंद और मूंग हलवा सहित अनेक पारंपरिक व्यंजन लोगों के लिए उपलब्ध रहे। खास बात यह रही कि हर स्टॉल पर लोगों की अच्छी भीड़ दिखाई दी। लोग परिवार और दोस्तों के साथ अलग-अलग व्यंजनों का स्वाद लेते नजर आए। महाराष्ट्र के पारंपरिक जायके और इंदौर के खानपान प्रेम का यह मेल जत्रा की खास पहचान बनकर उभरा।

नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, अश्लील वीडियो वायरल कर ब्लैकमेलिंग

इंदौर।

शहर के पास क्षिप्रा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित चार नाबालिगों को हिरासत में लिया है। आरोप है कि मुख्य आरोपी ने किशोरी का अश्लील वीडियो बनाया था, जिसके बाद उसके तीन साथियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मुख्य आरोपी समेत 4 नाबालिग हिरासत में

पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, जांच जारी

पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया और उसकी शिकायत के आधार पर पॉक्सो एक्ट सहित सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार नाबालिगों को हिरासत में लिया है। मामले में वीडियो वायरल किए जाने और आरोपियों की भूमिका सहित अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी छात्र है और उसके पिता की दुकान है। वहीं, अन्य तीन आरोपियों के परिवार खेती-किसानी से जुड़े हैं। चारों आरोपी नाबालिग हैं। पुलिस मामले में साक्ष्य जुटाकर आगे की कार्रवाई कर रही है। किशोरी की पहचान गोपनीय रखी गई है।

क्षिप्रा थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह मुकाती के मुताबिक, क्षिप्रा निवासी 16 वर्षीय किशोरी शनिवार रात परिजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 20 दिसंबर 2025 की शाम करीब 5 बजे उसका दोस्त वरुण उसे बूढ़ी बरलई स्थित अपने पिता की दुकान के पास ले गया था।

आरोप है कि वहां आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया और धोखे से उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण किशोरी ने तत्काल किसी को घटना की जानकारी नहीं दी।

तीन साथियों ने भी दी धमकी

पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी के तीन साथियों को भी वीडियो के बारे में पता चल गया था। आरोप है कि तीनों ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर किशोरी के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की। उन्होंने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बाद में किशोरी का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।

वीडियो वायरल होने के बाद किशोरी ने हिम्मत जुटाकर परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद परिजन शनिवार रात करीब 9 बजे उसे लेकर क्षिप्रा थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की।

हॉस्टल में चोरी, रनिंग करने गए छात्र तो चोर ले उड़ा 3 लैपटॉप, 3 मोबाइल और नकदी

इंदौर।

भंवरकुआं थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी स्थित देवनिवास हॉस्टल में चोरी की वारदात सामने आई है। शनिवार अलसुबह छात्र रनिंग करने के लिए कमरे से बाहर गए थे। इस दौरान कमरे का दरवाजा खुला रह गया। जब छात्र सुबह करीब 7 बजे लौटे तो कमरे से तीन लैपटॉप, तीन मोबाइल और नकदी गायब मिली। घटना के बाद छात्रों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रविवार को घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें एक संदिग्ध इलाके से निकलता दिखाई दे रहा है।

भंवरकुआं पुलिस के मुताबिक, सिवनी निवासी प्रिंस सराठे विष्णुपुरी स्थित देवनिवास हॉस्टल में अपने दोस्तों के साथ किराए से रहता है। 24 अक्टूबर



की तड़के प्रिंस अपने दोस्त मिहिर के साथ रनिंग करने ग्राउंड पर गया था। दोनों के जाने के दौरान कमरे का दरवाजा खुला रह गया। इसी बीच किसी ने कमरे में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। सुबह करीब 7 बजे दोनों वापस लौटे तो कमरे से सामान गायब मिला। प्रिंस का लैपटॉप, मिहिर, यशदीप और अयाज अंसारी के मोबाइल तथा सौरभ अहिरवार और युवराज के लैपटॉप चोरी हो चुके थे। युवराज का लैपटॉप एचपी कंपनी का था। कमरे में रखी नकदी भी नहीं मिली।

सामान गायब देखकर प्रिंस ने हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों को जगाया और उनसे पूछताछ की। हालांकि, किसी ने भी रात में किसी संदिग्ध के कमरे में आने की जानकारी होने से इनकार किया। इसके बाद छात्रों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। एक साथ कई कीमती इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी होने से हॉस्टल में रहने वाले छात्र परेशान हो गए।

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश

पुलिस को विष्णुपुरी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज मिले हैं। इनमें एक संदिग्ध इलाके से निकलता दिखाई दे रहा है। पुलिस फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने और उसकी तलाश में जुटी है। शनिवार रात मामले में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक, कुछ दिन पहले भी इलाके के हॉस्टलों से मोबाइल चोरी होने की घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है कि कहीं वारदातों के पीछे एक ही व्यक्ति या गिरोह तो नहीं है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज में विवाद

न्यूरोसर्जरी HOD पर रेजिडेंट डॉक्टरों के उत्पीड़न का आरोप, 7 दिन में कार्रवाई की मांग

इंदौर।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज और एमवाय अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में विभागाध्यक्ष डॉ. परेश सोंधिया के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टरों के उत्पीड़न की शिकायत के बाद विवाद गहरा गया है। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन (जूडा) ने डीन को पत्र लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और शिकायतकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि 7 दिन में लिखित जवाब और कार्रवाई नहीं होने पर सांकेतिक विरोध या हड़ताल की जा सकती है। वहीं, डॉ. सोंधिया ने आरोपों को निराधार और गलत बताते हुए खारिज किया है।



जूडा की शिकायत के मुताबिक, रेजिडेंट डॉक्टरों से सप्ताह में 140 से 150 घंटे तक अलावा अकादमिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से वंचित रखने की बात भी कही गई है। एसोसिएशन ने इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

रेजिडेंट डॉक्टरों ने विभागीय संसाधनों से जुड़े खर्च के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कराने की शिकायत भी की है। बताया गया है कि विभाग में पांच रेजिडेंट डॉक्टरों में से एक ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि अन्य डॉक्टरों के वार्ड छोड़ने की बात भी सामने आई है।

जूडा ने डीन से पूरे मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने और शिकायत करने वाले डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरी ओर, विभागाध्यक्ष ने आरोपों को गलत बताया है। अब मामले में कॉलेज प्रबंधन की जांच और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

परीक्षा और प्रशिक्षण में बाधा डालने की शिकायत

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि रेजिडेंट डॉक्टरों को स्थगित परीक्षा में फेल करने, प्रशिक्षण अवधि बढ़ाने और ऑपरेशन थिएटर (ह्रज़) में प्रवेश नहीं देने की धमकी दी जाती है। इसके

सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों के पालकों को मिलेगा 1 लाख का इनाम

27 अक्टूबर से प्रतियोगिता

इंदौर।

जिले में भारतीय नस्ल की उन्नत गायों के पालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोपाल कृष्ण ग्राम पुरस्कार योजना शुरू की जा रही है। वृंदावन ग्राम योजना के तहत 27 से 31 अक्टूबर तक जिले के चार गांवों में प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसमें सबसे ज्यादा दूध देने वाली गायों के पालकों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी।



पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक डॉ. दिनकर राव पाटील के मुताबिक, योजना के तहत रंगवासा, दतोदा, शिवनी और बनेड़िया गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें पात्र पशुपालकों का पंजीयन किया जाएगा। गायों के दुग्ध उत्पादन के आधार पर विजेताओं का चयन होगा।

प्रतिदिन 6 लीटर दूध देना जरूरी

प्रतियोगिता में उन्हीं पशुपालकों को शामिल होने का मौका मिलेगा, जिनके पास भारतीय नस्ल की उन्नत गाय है और जो प्रतिदिन कम से कम 6 लीटर दूध देती है। योजना का उद्देश्य देशी नस्ल की गायों के पालन को प्रोत्साहित करना और पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। पशुपालक पंजीयन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी संबंधित ग्राम या पशु चिकित्सा विभाग से प्राप्त कर सकते हैं।

रिसेप्शनिस्ट से अश्लील हरकतें करने वाले सब्जी व्यापारी पर एफआईआर

इंदौर।

शहर में महिलाओं से छेड़छाड़ के दो मामले सामने आए हैं। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट ने सब्जी व्यापारी पर अश्लील हरकतें करने और इशारे कर परेशान करने का आरोप लगाया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वहीं, लसूड़िया थाना क्षेत्र में 11वीं की छात्रा ने पूर्व सहपाठी पर फोन कर मिलने का दबाव बनाने की शिकायत की है। दोनों मामलों में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक, युवती फूटी कोठी स्थित एक निजी अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट है। अस्पताल के बाहर सब्जियों की दुकानें लगती हैं, जिनमें से एक दुकान नरेंद्र साहू की है। युवती का आरोप है कि आरोपी पिछले करीब 20

20 दिन से कर रहा था परेशान

छात्रा पर मिलने के लिए दबाव बनाने का आरोप

दूसरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। यहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने अपने पूर्व सहपाठी संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का आरोप है कि संजय आए दिन उसे मोबाइल पर कॉल कर परेशान करता था और मिलने की जिद करता था। शिकायत के मुताबिक, एक दिन पहले आरोपी छात्रा के घर के बाहर पहुंच गया और फोन कर उस पर जबरन मिलने का दबाव बनाने लगा। लगातार परेशान किए जाने से परेशान छात्रा ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंचे। शनिवार को लसूड़िया पुलिस ने आरोपी संजय के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की। पुलिस दोनों मामलों में शिकायती के आधार पर जांच कर रही है।

दिनों से उसे देखकर अश्लील इशारे करता था और गलत हरकतों से परेशान कर रहा था।

शनिवार रात युवती अस्पताल से बाहर निकली तो गार्ड उसे गेट तक छोड़ने आया। वह अपने भाई का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान आरोपी ने कथित तौर पर उसे अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया। युवती ने विरोध करते हुए उसे ललकारा, जिसके बाद अस्पताल का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया। इस बीच आरोपी वहां से भाग निकला।

घटना के बाद युवती अपनी बहन के साथ द्वारकापुरी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अब एआई से घर बैठे होगी आंखों की जांच

इंदौर। आंखों की बीमारी का पता लगाने के लिए अब मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने की मजबूरी कम हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से दूरदराज के गांवों में भी आंखों की स्क्रीनिंग और बीमारी की शुरुआती पहचान आसान बनाने की दिशा में काम हो रहा है। आने वाले 5 साल में नेत्र रोगों के डायग्नोसिस में एआई का इस्तेमाल और बढ़ने की उम्मीद है।रविवार को इंदौर में मध्यप्रदेश स्टेट ऑप्थैल्मोलॉजिकल सोसायटी की 49वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन विशेषज्ञों ने यह बात कही। तीन दिन तक चली इस कॉन्फ्रेंस में देशभर के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने आंखों की बीमारियों के आधुनिक इलाज, नई तकनीकों और चिकित्सा क्षेत्र में एआई की भूमिका पर चर्चा की। सम्मेलन में मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों से 700 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। अंतिम दिन तकनीकी सत्रों के साथ क्विज कॉम्पिटिशन और डेमो वर्कशॉप भी आयोजित की गई।

जमीन धोखाधड़ी के दो मामले, ब्रोकर पर 43.53 लाख हड़पने का आरोप

इंदौर।

शहर में जमीन और प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के दो मामले सामने आए हैं। क्राइम ब्रांच ने दोनों मामलों में शिकायतों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। पहले मामले में ब्रोकर पर प्लॉट बेचने के बाद 43 लाख 53 हजार रुपए की राशि अपने पास रखने का आरोप है। वहीं, दूसरे मामले में फर्जी दस्तावेजों और कथित जाली हस्ताक्षरों के आधार पर प्लॉट बेचने की कोशिश का खुलासा हुआ है।

क्राइम ब्रांच ने पुणे निवासी तनुजा सिद्धेश्वर की शिकायत पर न्यू बिजलपुर निवासी मोहित पिपले के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक, तनुजा ने संस्कृति पाम में स्थित प्लॉट नंबर 401 और 402 बेचने की जिम्मेदारी मोहित को दी थी। मोहित ब्रोकर का काम करता था और उसने इन प्लॉटों का सौदा 73 लाख 20 हजार रुपए में कराने की बात कही थी।

आरोप है कि मोहित ने पहले दोनों प्लॉटों की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, लेकिन सौदे की बची हुई 43 लाख 53 हजार रुपए की राशि तनुजा को नहीं दी। वह लगातार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। शिकायत में आरोप है कि उसने प्लॉटों का सौदा अन्य लोगों से कर उनकी रजिस्ट्री भी करवा दी और पूरी राशि खुद रख ली। जांच के बाद क्राइम ब्रांच ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है।

दूसरा मामला रानीपुरा निवासी कांच व्यापारी शाहिद उमर खां की शिकायत से जुड़ा है। शाहिद ने मयूर गृह निर्माण सहकारी संस्था का 900 वर्गफीट का प्लॉट एक डॉक्टर से खरीदा था। वर्ष 2024 में उन्हें पता चला कि जाकिर चौहान उक्त प्लॉट को अपना बताकर बेचने की कोशिश कर रहा है। शाहिद ने इस संबंध में जाकिर से बात की तो आरोप है कि उसने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दिया।

जांच में सामने आए कथित फर्जी हस्ताक्षर

शिकायत के मुताबिक, जाकिर ने दावा किया था कि प्लॉट उसकी पत्नी शमा बी के नाम पर है और उसने इसे सद्दाम पुत्र समसुद्दीन से खरीदा है। हालांकि, जांच में सामने आया कि सद्दाम संबंधित सहकारी संस्था का सदस्य नहीं था। जिन दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट का सौदा जाकिर के नाम दिखाया गया, उन पर संस्था के पदाधिकारियों के कथित फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। जांच में नोटरी से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल सामने आए। शिकायत के अनुसार, एक नोटरी ऐसे वकील के माध्यम से कराई गई थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जबकि दूसरी नोटरी वर्ष 2021 की दिखाई गई थी। क्राइम ब्रांच ने विस्तृत जांच के बाद जाकिर सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। दोनों मामलों में पुलिस आगे की जांच कर रही है।

नागरिकों को दिए वोट के अधिकार को छिनने का प्रयास-पटेल

देवास।

पिछले विगत कुछ सालों में जहां-जहां भाजपा की सरकारें बनीं, वो सभी वोट चोरी के जरिए ही बनीं है। चुनाव आयोग पर जो भी आरोप लगे हैं वे आरोप नहीं, बल्कि सच्चाई हैं। यह बात महाराष्ट्र के उप नेता प्रतिपक्ष आमीन पटेल ने कांग्रेस पर्यवेक्षक के तौर पर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के समक्ष कहीं। उन्होंने कहा कि आने वाले 1 नवंबर को नई दिल्ली के



रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक विशाल विरोध रैली का आयोजन किया गया है, उसमें देवास सहित मध्यप्रदेश और देश के तमाम भागों से लाखों की संख्या में कार्यकर्ता, दिल्ली में जुटेंगे और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे।

इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी का अड्डा बन चुका है। सवाल जब चुनाव आयोग से पूछे जाते हैं तो उसका जवाब बीजेपी के लोग सामने आकर देने लगते हैं। एसआईआर के चलते पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा चुनाव तक, हर स्तर पर वोट काटे गए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान जिला संगठन प्रभारी विनय बाकलीवाल, सुरेंद्र सिंह शेरा भैया, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रयास गौतम, जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष मनीष चौधरी विशेष तौर पर उपस्थित रहें। उक्त जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता हारिस गजधर ने दीं।

बेकाबू कार ने 3 को रौंदा, मौत

इंदौर से पिकनिक मनाने आया था आरोपी

देवास।



जिले के ग्रामीण क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी दो महिलाओं को रौंद दिया। इसके बाद घर के बाहर कुर्सी पर बैठे 80 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी। फिर कार सीधे पेड़ से जा टकराई। हादसे में बुजुर्ग और दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान देवनालिया-जुनापानी इलाके के रहने वाले 80 वर्षीय शंकर, 40 वर्षीय मनीबाई और 45 वर्षीय जमुनाबाई के रूप में हुई है। हादसा रविवार को उदयनगर थाना क्षेत्र के दड़ गांव के पास हुआ। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पूरी घटना वहां मौजूद सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना में आसपास की झुग्गी-झोपड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। दूसरे सीसीटीवी में सड़क पर कुर्सी पर बैठा बुजुर्ग दिख रहा है, तेज रफ्तार कार बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद पेड़ से टकरा गया। जानकारी के मुताबिक, कार सवार इंदौर के रेसकोर्स रोड इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वे रविवार सुबह पिकनिक मनाने उदयनगर आए थे। सुबह करीब 11 बजे दड़ गांव के पास उनकी कार तेज रफ्तार में थी। तभी अचानक कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी मनीबाई और जमुनाबाई को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी गंभीर रुप से घायल हो गई। इसके बाद भी कार नहीं रुकी। घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर धूप सेंक रहे 80 वर्षीय शंकर को रौंदते हुए कार पेड़ से जा टकराई। हादसे के बाद अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने महिला और बुजुर्ग दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि अनियंत्रित होने के बाद उसने सड़क किनारे लगे तीन से चार खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे में कार चालक भी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।



गजरा गियर्स चौराहे पर निगम ने की अस्थाई अतिक्रमण हटाने कार्यवाही

देवास। निगमायुक्त दलीप कुमार के निर्देशन में शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाए रखने तथा आम नागरिकों के आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लगातार अस्थाई अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है साथ ही निगम संबंधि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। इसी कडी में शनिवार 24 अक्टूबर को निगम रिमूवल एवं लोक निर्माण की टीम द्वारा संयुक्त रूप से गजरा गियर्स चौराहे पर कार्यवाही करते हुए सडक़ किनारे लगे अस्थाई अतिक्रमण, ठेले-गुमटियों एवं अवैध रूप से रखे सामानों को हटाया गया। कार्यवाही से चौराहे पर यातायात व्यवस्था सुगम हुई। आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे सडक़ व फुटपाथ पर अतिक्रमण न करें एवं शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। कार्यवाही के दौरान अस्थाई अतिक्रमण प्रभारी हेमंत उबनारे, उपयंत्री करुणा दसोरिया, रिमूवल दरोगा अबरार खान, हितेश पटेल सहित निगम का अमला मौजूद रहा।

भामसं ने शस्त्र पूजन व राम रक्षा स्त्रोत का पाठ कर मनाया दशहरा मिलन समारोह

देवास।

भारतीय मजदूर संघ द्वारा दशहरा मिलन समारोह का आयोजन सम्पन्न हुआ। जिलामंत्री महेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि समारोह में मध्य प्रदेश कंस्ट्रक्शन मजदूर महासंघ के प्रदेश महामंत्री एवं मध्य प्रदेश कर्मकार कल्याण मंडल के सदस्य लोकेश विजयवर्गीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष धनंजय गायकवाड़ ने की तथा विभाग प्रमुख राजू लोधी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, भगवान विश्वकर्मा एवं भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक राष्ट्रऋषि दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्रों पर माल्यार्पण कर किया गया। इसके पश्चात शस्त्र पूजन, भारत माता की



आरती और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ किया गया। उपस्थित श्रमिकों को विजय तिलक लगाकर दशहरे की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में श्रमिकों की एकता, सम्मान और अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष धनंजय गायकवाड़ ने कहा कि भगवान श्रीराम ने असत्य पर सत्य और अन्याय पर न्याय की विजय स्थापित की। इसी प्रकार भारतीय मजदूर संघ श्रमिकों के हक और सम्मान के लिए कार्य करता है। हमारा संकल्प देश हित, उद्योग हित और मजदूर हित है। अखिल भारतीय स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन की सभी समितियां एकजुट होकर श्रमिकों के हितों की रक्षा कर रही हैं। एकता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। कार्यक्रम में दिलीप चौहान, विनोद पांडे, कल्याण गौड़, प्रमोद आचार्य, नारायण वर्मा, चूड़ामणि मोरे, नरेंद्र मिश्रा, देवी सिंह दागा पाटिल, चंद्रकांत सोनी, रामचंद्र गौड़, विक्रम गौड़, दिलीप तिवारी, नीरज तिवारी, निर्भय चौहान, विनोद चौधरी, जयराम परिहार, अनिल सोनी, धर्मेंद्र परिहार, शरद सरोषी, शिवाजीराव, अर्जुन सिंह यादव, बालमुकुंद मोदी एवं अतुल विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और श्रमिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला मंत्री महेंद्र सिंह परिहार ने किया तथा आभार जीवन सिंह मेहरा ने माना।

मुखर्जी नगर में सुनी गई 'मन की बात'

देवास।



मुखर्जी नगर, देवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 139वें संस्करण को बूथ क्रमांक 121 पर विश्वामित्र अवॉर्डी एवं भारतीय सॉफ्ट टेनिस कोच सुदेश सांगते जी के निवास पर सुना गया। इस अवसर पर एशियन गेम्स (जापान) में सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी जय मीणा जी, योगेश जी, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी यशपाल सिंह पंवार , निपुण सांगते, आकाश जी एवं हिमांशु शर्मा उपस्थित रहे। सभी ने प्रधानमंत्री के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम में जिला महामंत्री राजेश यादव , जिला मंत्री कपिल सिंह पंवार , पार्षद प्रतिनिधि अजब सिंह ठाकुर जी एवं भाजपा नेता मनीष जैन जी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उक्त जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कमल अहिरवार ने दी।

स्वामित्व योजना के तहत 25 से 31 तक विशेष शिविर आयोजित

नीमच। स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 के तहत नीमच जिले में 25 से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में तैयार अधिकार अभिलेखों के आधार पर संबंधित संपत्तियों के दस्तावेजों का निःशुल्क निष्पादन एवं पंजीयन सुनिश्चित करना है। जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी अपने क्षेत्र में शिविरों के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे। वे जनप्रतिनिधियों को शिविरों की जानकारी देकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। शिविरों की निगरानी एवं निरीक्षण के लिए भी अधिकारियों को नामांकित किया जाएगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पंचायत समन्वय अधिकारी तथा सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

नशा मुक्तयुवा फॉर विकसित भारत' थीम पर आस-पड़ोस युवा संसद का आयोजन

धार।



युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के 'मेरा युवा भारत' धार के तत्वावधान में बदनावर ब्लॉक के सेंट जोसेफ विजिटेशन स्कूल में 'आस-पड़ोस युवा संसद' कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य विषय 'नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत' रहा। कार्यक्रम में 'मेरा युवा भारत' धार की जिला युवा अधिकारी सुश्री दीर्घा राजावत के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान जिला युवा अधिकारी दीर्घा राजावत ने 'मेरा युवा भारत' (माई भारत) संगठन की रूपरेखा, उद्देश्यों और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

गरोठ में एम्बुलेंस के भीतर हुआ सुरक्षित प्रसव

मंदसौर।

मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ तहसील अंतर्गत आने वाले पिपलिया जत्ती गांव में 108 एम्बुलेंस सेवा की त्वरित सूझबूझ और तत्परता से एक महिला का एम्बुलेंस के अंदर ही सुरक्षित प्रसव कराया गया। जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना का विवरणपिपलिया जत्ती निवासी मनीषा (पहिचान- पति अर्जुन, उम्र 23 वर्ष, जाति मेघवाल) को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। परिजनों द्वारा तुरंत सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर 108 पर संपर्क किया गया। सूचना मिलते ही सीएचसी (ष्ट.ाष्ट्र) शामगढ़ की एएलएस (ऋ) लोकेशन की एम्बुलेंस बिना देर किए पिपलिया जत्ती गांव के लिए रवाना हो गई। एम्बुलेंस स्टाफ ने महिला को तुरंत वाहन में शिफ्ट किया और



गरोठ सिविल अस्पताल के लिए लेकर निकले। हालांकि, अभी वे गांव के बाहर ही पहुंचे थे कि महिला को प्रसव पीड़ा अत्यधिक बढ़ गई। कर्मचारियों की सूझबूझ से बची जानस्थिति की गंभीरता को भांपते हुए एम्बुलेंस में तैनात इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मुकेश दांगी और पायलेट विजय मालवीया ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए गाड़ी को रास्ते में ही रोक दिया और सुरक्षित डिलीवरी कराने का निर्णय लिया। दोनों स्वास्थ्यकर्मियों के बेहतरीन प्रयासों और पेशेवर सूझबूझ से महिला ने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। अस्पताल में भर्ती और सराहनाप्रसव के बाद एम्बुलेंस स्टाफ द्वारा जच्चा और बच्चा दोनों को पूरी सावधानी के साथ सिविल हॉस्पिटल गरोठ में सुरक्षित भर्ती कराया गया। वर्तमान में महिला और नवजात शिशु दोनों स्वस्थ्य हैं। समय पर मिली इस जीवनरक्षक चिकित्सा सेवा के लिए महिला और उनके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस सेवा तथा उसमें तैनात पूरी टीम का आभार व्यक्त किया और उनकी सराहना की।

चंदाना एवं बिंजाना प्रकरण के लिए जाँच दल गठित

15 दिन में प्रस्तुत करेंगे रिपोर्ट

देवास। ग्राम चंदाना एवं बिंजाना में की घटना गंभीरता से लेते हुए संभागायुक्त, उज्जैन द्वारा एक उच्चस्तरीय संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। जारी आदेश के अनुसार, घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए मृत्यु के कारणों, परिस्थितियों तथा संबंधित सभी तकनीकी व प्रशासनिक तथ्यों की विस्तृत एवं निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। जांच दल में प्रशासनिक, पुलिस, आबकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। उक्त दल के अध्यक्ष श्री प्रथम कौशिक (भा.प्र.से.), अपर कलेक्टर, उज्जैन होंगे। जांच दल में श्री रामसनेही मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (गरोठ), मंदसौर, लेखराज मीणा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी), सैलाना, रतलाम, हर्षवर्धन राय, उप आबकारी आयुक्त, संभागीय उडऩदस्ता, उज्जैन, डॉ. दीपक कुमार पिप्पल, क्षेत्रीय संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उज्जैन सदस्य होंगे।



किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

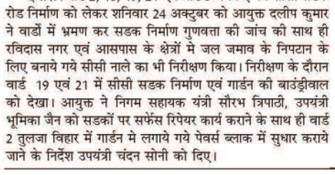
मंदसौर।

मंदसौर जिले में रबी फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। किसान आसानी से सभी प्रकार के उर्वरक प्राप्त कर सकें इसके लिए वितरण व्यवस्था को और आसान किया जा रहा है। कलेक्टर दिव्यांक सिंह द्वारा रविवार को कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में भारतीय किसान संघ के जिले के पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कार्य योजना तैयार की गई। किसानों को बगैर परेशानी के आसानी से उर्वरक उपलब्ध हो सके इसकी रूपरेखा कलेक्टर द्वारा निर्धारित की गई। बैठक में भारतीय किसान संघ के जिला पदाधिकारी भंवर सिंह पवार, प्रीतिपाल सिंह देवड़ा, सु आशा कुंवर राठौर, राधेश्याम भाटी, बालेश्वर पाटीदार, प्यारचंद भारती, सु शकुंतला परमार, भंवर लाल शर्मा, मोहनलाल बोडाना, उपसंचालक कृषि रविंद्र मोदी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक सुनील कछारा, मार्केटिंग फेडरेशन जिला अधिकारी सु गरिमा सेंगर, एमपी एग्रो के अग्रवाल के अलावा सहकारिता आदि अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसान कम से कम समय में आसानी से सभी प्रकार के उर्वरक प्राप्त कर सके। इसके लिए चौकस रहकर गंभीरता से कार्य करें। नगद विक्रय केंद्रों के समय में भी वृद्धि की जा रही है। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि अब जिले के नगद विक्रय केंद्र प्रातः 8:00 बजे से कार्य करेंगे।

नरवाई प्रबंधन हेतु स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

धार।

कृषि अभियांत्रिकी विभाग, जिला धार द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे कंबाइन हार्वेस्टर से फसल कटाई के दौरान फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन तथा नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए स्ट्रॉ मैनेजमेंट स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम कंबाइन हार्वेस्टर के पीछे लगाया जाने वाला एक विशेष उपकरण है, जो फसल कटाई के दौरान खेत में बचे फसल अवशेषों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर खेत में समान रूप से फैला देता है। इससे फसल अवशेषों का खेत में ही प्रबंधन करना आसान होता है तथा नरवाई जलाने की आवश्यकता कम होती है।सहायक कृषि यंत्री, जिला धार ने बताया कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम पर अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए 21 अक्टूबर 2026 से ई-कृषि अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए कृषकों को 3,500 की धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (ष्ठ्ठ) सहायक कृषि यंत्री, धार के नाम से बनवाकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित धरोहर राशि के डिमांड ड्राफ्ट के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। कृषि अभियांत्रिकी विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें तथा फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर नरवाई जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकने में सहयोग करें।



आयुक्त ने किया सड़क निर्माण कार्यो का निरीक्षण

देवास। वार्ड 2, 18, 19, 21 एवं वार्ड 5 में किए गये सीसी सडक रोड निर्माण को लेकर शनिवार 24 अक्टूबर को आयुक्त दलीप कुमार ने वार्डों में भ्रमण कर सडक निर्माण गुणवत्ता की जांच की साथ ही रविदास नगर एवं आसपास के क्षेत्रों मे जल जमाव के निपटान के लिए बनाये गये सीसी नाले का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड 19 एवं 21 में सीसी सडक निर्माण एवं गार्डन की बाउंड्रीवाल को देखा। आयुक्त ने निगम सहायक यंत्री सौरभ त्रिपाठी, उपयंत्री भूमिका जैन को सडकों पर सर्फेस रिपेयर कार्य कराने के साथ ही वार्ड 2 तुलजा विहार में गार्डन मे लगाये गये पेवर्स ब्लाक में सुधार कराये जाने के निर्देश उपयंत्री चंदन सोनी को दिए।

मुख्यमंत्री के नलखेड़ा कार्यक्रम की तैयारी का कलेक्टर ने लिया जायजा

सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समय-सीमा में निर्वहन करने के निर्देश

आगर मालवा।

प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज दोपहर में नलखेड़ा पहुंचकर शासन द्वारा स्वीकृत माँ बगलामुखी देवी लोक के तहत 85.40 करोड़ रुपये की लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि-पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने आज रविवार को सुबह नलखेड़ा पहुंचकर मंदिर परिसर के समीप प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सभा पंडाल निर्माण, भूमि-पूजन कार्यक्रम की तैयारी, मंच निर्माण, कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले विशिष्ट जनों, जनप्रतिनिधियों, प्रेस जगत/मीडिया के साथियों, ग्रामीण जनों,



महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक-पृथक सेक्टर निर्माण कर उनकी बैठक व्यवस्था, वाहनों की सुगम पार्किंग व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल पर पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई व्यवस्था, सुविधाजनक ढंग से आमजनों के प्रवेश एवं कार्यक्रम स्थल से निकासी की व्यवस्था, निर्बाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था, अस्थाई सुविधाघर की व्यवस्था सहित कार्यक्रम के सफल आयोजन के संबंध में सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने मौके पर उक्त व्यवस्थाओं का अवलोकन कर जायजा लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ बी.एस. सोलंकी, एसडीएम कमल मंडलोई, श्रीमती देव कुमार सोलंकी, एसडीओपी देवनारायण यादव, तहसीलदार प्रियांक श्रीवास्तव, सीएमओ सुश्री मिनी अग्रवाल सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने नगर पालिका कार्यालय नलखेड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अधिकारियों से संवाद कर मुख्यमंत्री कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने वी.सी. के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सोमवार को नलखेड़ा कार्यक्रम में अधिकाधिक हितग्राहियों एवं क्षेत्र के ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यक्रम में आने वाले हितग्राहियों एवं ग्रामीण जनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने मंच निर्माण स्थल, पंडाल निर्माण एवं बेरीकेटिंग, पार्किंग स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक के पहुँच मार्ग का समतलीकरण करवाने, पार्किंग स्थल पर आवश्यक साफ-सफाई एवं समतलीकरण करवाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम स्थल, पार्किंग स्थल एवं हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक विभिन्न स्थानों पर सुगम यातायात की दृष्टि से आवश्यक सुरक्षा पॉइंट पर आवश्यक कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

न्यूज ब्रीफ

नियम तोड़ने पर कार्रवाई, कार्बाइड गन पर विशेष नजर

उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में त्योहार के दौरान आगजनी और विस्फोट जैसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखा दुकानों की जांच की। दीपावली के दौरान खतरनाक उपकरणों के इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प जैसे उपकरणों की बिक्री एवं उपयोग पर लागू प्रतिबंधों का पालन करने की हिदायत दी है। इन उपकरणों के इस्तेमाल से हादसों का खतरा हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने दुकानदारों को प्रतिबंधित उपकरणों की बिक्री नहीं करने और नियमों का उल्लंघन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इस बार प्रशासन हाई अलर्ट पर है और चप्पे-चप्पे की निगरानी कर रहा है। इस दौरान दुकानदारों को वैध लाइसेंस, अग्नि सुरक्षा और विस्फोटक सामग्री के भंडार से जुड़े नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कार्बाइड गन और कार्बाइड लैम्प जैसे खतरनाक उपकरणों की बिक्री और उपयोग पर लागू प्रतिबंधों का पालन करने की हिदायत भी दी गई।

संभागायुक्त सिंह ने निर्माण कार्यों की समीक्षा की



उज्जैन। संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह एवं कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने नगर निगम द्वारा कराए जा रहे एमआर-4 एवं एसआर-1 सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान संभागायुक्त आशीष सिंह ने मौके पर उपस्थित नगर निगम के इंजीनियरों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सिंहस्थ-2028 के लिए निर्माण कार्यों को जल्द पूर्ण करें। इसलिए सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए तथा किसी भी कारण से कोई भी कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पर्याप्त संख्या में टीमें लगाकर कार्य की गति बढ़ाई जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो सके। संभागायुक्त आशीष सिंह एवं कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने सबसे पहले ढांचा भवन से एमआर-5 तक किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान आमजन को वैकल्पिक मार्ग की जानकारी देने वाले स्पष्ट एवं पर्याप्त संख्या में साइनेज लगाए जाएं, ताकि निर्माण कार्य के दौरान नागरिकों को आवागमन में असुविधा न हो। इसके पश्चात नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन 30 मीटर चौड़े एसआर-1 सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मौके पर निर्माण कार्य की प्रगति, अब तक पूर्ण किए गए कार्य तथा आगामी कार्य योजना और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जानकारी ली। संभागायुक्त सिंह ने निर्देश दिए कि एसआर-1 सड़क निर्माण कार्य में अलग-अलग टीमें लगाकर कार्य को गति दी जाए।

अब भूमिपूजन के साथ ही एयरपोर्ट को मिलेगी नई उड़ान

देशभर से महाकाल के दर्शन करने आने वालों को मिलेगी सुविधा, जल्द होगा भूमिपूजन

उज्जैन।



दताना हवाई पट्टी के आसपास उपलब्ध 150 एकड़ जमीन पर शुरुआती काम कराने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में परियोजना का भूमिपूजन कराने की तैयारी है। भूमिपूजन की तारीख तय होना बाकी है। बाउंड्रीवॉल निर्माण के साथ काम शुरू किया जाएगा। एयरपोर्ट बनने से उज्जैन देश के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ सकेगा। इससे महाकाल दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। खासकर सिंहस्थ-2028 के दौरान देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की आवाजाही आसान बनाने में यह परियोजना महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इतिहासजानें

प्रशासन ने उज्जैन में करीब 450 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट विकसित करने की योजना तैयार की है। पहले चरण में दताना हवाई पट्टी के आसपास 150 एकड़ जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है। शेष 300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह के अनुसार, एएसपी के लिए भूमिपूजन की तैयारी की जा रही है। शुरुआत बाउंड्रीवॉल निर्माण से होगी। इसके बाद ही शेष भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

उज्जैन एयरपोर्ट परियोजना के लिए मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल 590 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत कर चुका है। सरकार का लक्ष्य सिंहस्थ-2028 से पहले एयरपोर्ट को क्रियाशील बनाना है। परियोजना के तहत टर्मिनल भवन के विकास, आधुनिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) व्यवस्था, अग्निशमन केंद्र और यात्रियों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। एयरपोर्ट की वास्तविक क्षमता, उड़ानों का संचालन और निर्माण के विभिन्न चरणों की समयसीमा संबंधित विभागों की आगे की कार्ययोजना पर निर्भर करेगी।

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी सुविधा

सिंहस्थ-2028 के दौरान उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में एयरपोर्ट विकसित होने से हवाई यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उज्जैन पहुंचने में सुविधा मिल सकती है। वर्तमान में हवाई यात्रा के लिए दूसरे शहरों के एयरपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है।

पर्यटन को बढ़ावा

एयरपोर्ट शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ कारोबार, होटल उद्योग, परिवहन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाजाही के लिए भी हवाई सुविधा उपयोगी हो सकती है।

बाउंड्रीवॉल से काम

कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि उज्जैन एयरपोर्ट विकसित करने के लिए भूमिपूजन की तैयारी की जा रही है। बाउंड्रीवॉल निर्माण के साथ काम शुरू किया जाएगा। शेष जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई भी जारी है। उम्मीद है जल्द ही भूमिपूजन शुरू होगा।

सिंहस्थ-2028 में टेंट सिटी की नई पहल

किसानों की सहभागिता से आकार लेगी आवासीय व्यवस्था

उज्जैन।

सिंहस्थ-2028 के आयोजन को भव्य एवं सुव्यवस्थित बनाने के साथ श्रद्धालुओं के लिए आवासीय सुविधाओं के विस्तार की दिशा में प्रशासन द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सिंहस्थ-2028 के दौरान टेंट सिटी विकसित किए जाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श के लिए संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह एवं कलेक्टर रौशन कुमार सिंह की उपस्थिति में किसानों एवं प्रशासन के बीच बैठक आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय किसान, जिला प्रशासन, पुलिस विभाग तथा पर्यटन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सिंहस्थ मेला कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में पर्यटन विभाग के सहयोग एवं स्थानीय किसानों की सक्रिय सहभागिता से सिंहस्थ-2028 के दौरान टेंट सिटी विकसित करने के संबंध में सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक में टेंट सिटी के संभावित विकास, संचालन एवं आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में किसानों की भूमि, सुविधाओं एवं हितों को प्राथमिकता देते हुए टेंट सिटी के विकास की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई। प्रशासन की ओर से किसानों को टेंट सिटी की अवधारणा, संभावित व्यवस्थाओं तथा इससे मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी गई। साथ ही उपस्थित किसानों से उनके सुझाव, अपेक्षाएं एवं आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा की गई। किसानों ने टेंट सिटी विकसित करने की पहल में रुचि व्यक्त करते हुए अपनी सहभागिता के लिए सकारात्मक सहमति जताई। किसानों ने भूमि के उपयोग, आवश्यक सुविधाओं, संचालन व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव भी साझा किए। उनके सुझावों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों के समन्वय से आगामी कार्ययोजना तैयार किए जाने पर चर्चा हुई। बैठक में अपर मेला अधिकारी ओम प्रकाश सनोडिया, एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौर, एएसपी मनोज खत्री सहित पर्यटन विकास निगम के अधिकारी एवं क्षेत्रीय किसान उपस्थित रहे। संभागायुक्त आशीष सिंह एवं कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बैठक में किसानों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके सुझावों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही किए जाने की दिशा में चर्चा की।



रोजगार एवं सेवाओं के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा

स्थानीय किसानों को मिलेंगे आर्थिक अवसर सिंहस्थ-2028 के दौरान टेंट सिटी विकसित करने की पहल से एक ओर जहां देश-विदेश एवं विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त एवं सुविधाजनक आवासीय व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी, वहीं दूसरी ओर स्थानीय किसानों की सहभागिता सुनिश्चित होने से उन्हें आर्थिक अवसर भी प्राप्त होंगे। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं विभिन्न प्रकार की सेवाओं के अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रशासन द्वारा इस पूरी पहल में किसानों के हितों एवं सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर टेंट सिटी के विकास एवं संचालन से जुड़ी आवश्यक व्यवस्थाओं पर आगामी चरण में कार्य किया जाएगा।

कलेक्टर ने इंटीरियर कार्य का किया निरीक्षण



उज्जैन। कलेक्टर रौशन कुमार सिंह एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, श्रीमती नेहा जैन द्वारा आज विक्रम कीर्ति संग्रहालय में संचालित इंटीरियर कार्यों का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नेहा जैन द्वारा कलेक्टर को कार्यस्थल की वर्तमान स्थिति एवं कार्यों की प्रगति से अवगत कराया गया। साथ ही, संग्रहालय की गैलरी की छत पर किए गए रंग-रोगन का अवलोकन कराया। कलेक्टर द्वारा संग्रहालय की गैलरियों एवं वहां प्रदर्शित कलाकृतियों (आर्टिफैक्ट्स) के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तथा कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को संग्रहालय के समस्त इंटीरियर कार्य 15 दिसंबर 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निर्देशित किया कि कार्यों की गति एवं गुणवत्ता पर समान रूप से विशेष ध्यान दिया जाए तथा प्रत्येक कार्य की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण हो सके।



अतिरिक्त सचिव ने नवसाक्षरों के परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण

उज्जैन।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अतिरिक्त सचिव श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी ने शनिवार को 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असाक्षरों को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित नवसाक्षर मूल्यांकन परीक्षा के परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।

अतिरिक्त सचिव श्रीमती शर्मा अवस्थी ने जिले के शासकीय माध्यमिक विद्यालय पालखेदा एवं शासकीय माध्यमिक विद्यालय नरवर स्थित परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने केंद्रों पर उपस्थित परीक्षार्थियों से चर्चा कर परीक्षा के संबंध में जानकारी ली तथा व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। परीक्षा केंद्रों पर नवसाक्षर परीक्षार्थियों में विशेष उत्साह देखने को मिला। सामाजिक चेतना केंद्र पर साक्षरता की परीक्षा देने पहुंचे बुजुर्ग परीक्षार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। परीक्षार्थियों ने उत्साहपूर्वक परीक्षा में भाग लिया। निरीक्षण के दौरान एक विशेष संयोग भी देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में बहू ने अक्षर साथी के रूप में अपनी सास की नवसाक्षर मूल्यांकन परीक्षा ली।

यह दृश्य उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के उद्देश्य और सामाजिक सहभागिता का प्रेरक उदाहरण रहा। जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी संजय शर्मा ने बताया कि कलेक्टर रौशन कुमार सिंह एवं जिला पंचायत सीईओ श्रेयांश कुमट के मार्गदर्शन में जिले में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार नवसाक्षर मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन किया गया। जिले में कुल 70 हजार 220 परीक्षार्थियों ने 1263 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा दी। शर्मा ने बताया कि परीक्षा में 15 वर्ष से लेकर बुजुर्ग आयु वर्ग तक के परीक्षार्थियों ने अपनी सुविधा के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के मध्य एक घंटे की लिखित परीक्षा दी।

दो साल से पहले उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन बनकर हो गया तैयार, अब जल्द शुभारंभ

सिक्स लेन पर बिना रुके ही कट जाएगा टैक्स

उज्जैन।

उज्जैन से इंदौर तक सिक्स लेन पर अब गाड़ियां सरपट दौड़ने लगी हैं। जल्द ही इसका विधिवत लोकार्पण भी करने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद लोगों की जेब भी हल्की होगी क्योंकि सिक्स लेन के हिसाब से टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी नई दर सामने नहीं आई है परंतु जल्द ही इसका निर्धारण हो जाएगा। टोल नाका भी एक ही जगह निनोरा में रहेगा, जहां गाड़ियों का बिना रुके टोल कट जाएगा।

अगले माह नए सिक्स लेन का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। इसके लिए तारीख निर्धारित करने की कवायद भी की जा रही है। तारीख तय होते ही विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने इसका भूमिपूजन 19 सितंबर 2024 को किया था और आधिकारिक रूप से 15 जनवरी 2025 से काम शुरू किया गया था। इस हिसाब से रोड का काम 2 साल से पहले शुरू होने जा रहा है। शुभारंभ के साथ ही इस पर टोल राशि भी ज्यादा देनी पड़ेगी। एमपीआरडीसी



अधिकारियों के अनुसार अब सिक्स लेन के मानदंड के अनुसार ही टोल राशि तय की जाएगी जो वर्तमान दर से अधिक होगी। राहत की बात यह होगी कि टोल एक ही जगह निनोरा में देना पड़ेगा। इंदौर सीमा में बारोली स्थित टोल बंद खत्म हो जाएगा। इसके लिए निनोरा में नया टोल बनाने की भी तैयारी शुरू हो गई है।

लवकुश चौराहे तक 30 मिनट से कम समय में पहुंच रही गाड़ियां उज्जैन से इंदौर के लवकुश चौराहा तक गाड़ियां अब 30 मिनट या उससे भी कम समय में पहुंच रहीं। इंदौर में लवकुश ब्रिज की एक भुजा चालू होने से इंदौर का सफर तेज रफ्तार से हो रहा। इससे सिंहस्थ में उज्जैन आने वाले लोगों को तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का एक अलग अनुभव होगा।

एटीएमएस टोल बूथ की योजना है सिक्स लेन पूरा होने के बाद टोल भी उसी के अनुसार लगेगा। टोल बूथ

निनोरा में एक ही जगह होगा टोल बूथ

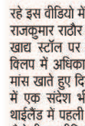
निनोरा में सिक्स लेन का केवल एक ही टोल बूथ होगा। एमपीआरडीसी इसे एटीएमएस बनाने की कोशिश कर रहा। एटीएमएस यानी एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट टोल टैक्स। हाइवे सुरक्षा के मामले में इसे एटीएमएस कहा जाता है। यह एक आधुनिक एआई (एआई) और कैमरों पर आधारित सिस्टम है। इस सिस्टम में हाईवे पर हाई-टेक एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे और सेंसर लगाए जाते हैं। इससे जब गाड़ी हाईवे से गुजरती है, तो कैमरे नंबर प्लेट और फास्टैग को स्कैन कर लेते हैं और गाड़ी को बिना रोके टोल काट लेते हैं। यदि कोई वाहन ओवरस्पीडिंग (तय गति से तेज़ चलना), गलत लेन में गाड़ी चलाना या बिना सीट बेल्ट के पाया जाता है, तो यह सिस्टम ऑटोमैटिक उसका चालान भी जनरेट कर देता है।

एक ही रहेगा, जो निनोरा में ही रहेगा जहां एटीएमएस प्लान है। बूथ का काम भी शुरू हो गया है। रोड का काम फिनिशिंग में चल रहा है।

थाईलैंड में मगरमच्छ का मांस खाना पड़ा भारी

बिना अनुमति जाने पर होगी कार्रवाई

उज्जैन। नगर निगम के एक भवन अधिकारी बिना विभागीय स्वीकृति विदेश यात्रा पर जाने और थाईलैंड में मगरमछ का मांस खाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासनिक कार्रवाई की जद में आ गए है। नगर निगम प्रशासन ने बिना पूर्व अनुमति विदेश यात्रा पर जाने को बेहद गंभीरता से लिया है। आरोपी अधिकारी के खिलाफ सेवा नियमों के उल्लंघन के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पूरी तैयारी की जा रही है।



सोशल मीडिया पर तेजी से साझा हो रहे इस वीडियो में नगर निगम में कार्यरत भवन अधिकारी राजकुमार राठौर अपनी पत्नी के साथ एक रेस्तरां अथवा खाद्य स्टॉल पर बैठे नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो क्लिप में अधिकारी अपनी पत्नी के साथ मगरमच्छ का मांस खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पर अंग्रेजी भाषा में एक संदेश भी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है कि थाईलैंड में पहली बार मगरमछ का मांस आजमाते हुए। जैसे ही यह वीडियो सार्वजनिक मंचों पर सामने आया, वैसे ही अधिकारी की इस विदेश यात्रा और उनके आचरण को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चाएं शुरू हो गईं। शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए किसी भी विदेशी दौरे पर जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से लिखित स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होता है। हालांकि भवन अधिकारी ने विदेश जाने के लिए निर्धारित प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। वीडियो सार्वजनिक होने के बाद जब मामले की प्राथमिक जांच की गई, तो पता चला कि अधिकारी ने केवल अवकाश स्वीकृत कराया था, लेकिन अपने आवेदन में कहीं भी देश से बाहर जाने की जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी।

दो मंजिला संत भवन, 3 घंटे में हो गया खंडहर



उज्जैन।

सिंहस्थ क्षेत्र अंकपात रोड स्थित 11 मुखी विराट हनुमान मंदिर परिसर में साधु संतों के लिए बनाए जा रहे भवन पर नगर निगम ने आज सुबह कार्रवाई कर दी। 1 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया यह भवन केवल तीन घंटे में ही खंडहर में बदल गया। निगम अधिकारियों के अनुसार सिंहस्थ क्षेत्र में होने के कारण 9 माह पहले ही नोटिस दे दिया था।

सुबह करीब 6 बजे जब निगम का अमला मंदिर के बाहर पहुंचा और मेन गेट खुलते ही दो जेसीबी से भवन में तोडफ़ोड़ शुरू कर दी। सुबह 9 बजे तक आधे से ज्यादा भवन खंडहर में बदल गया था। निगम के अधीक्षण यंत्री प्रमोद मालवीय ने बताया सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण होने के कारण यह कार्रवाई की गई है। जनवरी में ही नोटिस दे दिया था।

बाहर से धर्मशाला और अंदर से होटलनुमा कमरे- मंदिर परिसर में करीब 4 हजार वर्गफीट जमीन पर निर्माणाधीन संत निवास (धर्मशाला) में 20 रूम बनाए गए थे। इस पर एक करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। कार्रवाई के दौरान एक निगम कर्मी ने बताया बाहर से तो धर्मशाला दिखाई दे रहा था और अंदर होटल जैसे कमरे हैं। महावीरदास जी ने बताया इसके लिए एक करोड़ रुपए मांग मांग कर इकट्ठे किए थे। कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स के साथ अमला सुबह करीब 5 बजे मंदिर के गेट पहुंचा, लेकिन 10 फीट ऊंचे गेट पर ताला अंदर से लगा था। निगम अधिकारियों ने गेट के खटखटाया लेकिन कोई नहीं आया तो एक निगम कर्मी गेट के ऊपर चढ़ा और अंदर पहुंचा, लेकिन तब तक मंदिर के सेवक केशरीनाथ आ चुके थे। ताला खुलते ही टीम अंदर पहुंची और काम शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने पहले देखा कि अंदर कोई है तो नहीं फिर जेसीबी बुलाई और तोडफ़ोड़ शुरू कर दी।

वीडियो कॉल कर नृसिंहदास जी को दिखाया दृश्य

जेसीबी और अमला देख मंदिर के महामंडलेश्वर महावीरदास जी सकते में आ गए। उन्हें यकीन ही नहीं था कि निगम की टीम इस तरह आ धमकेगी। निगम अधिकारियों ने कहा आप एक तरफ हो जाइए, नहीं तो मलबा ऊपर आ जाएगा। बाद में केशरीनाथ ने वीडियो कॉल कर नृसिंहदास महाराज को कार्रवाई का दृश्य दिखाया। सुबह का समय होने और किसी से बात न होने पर महावीरदास जी केशरीनाथ के साथ अपने कक्ष में पहुंच गए।

सीएमएचओ डॉ. विक्रम रघुवंशी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंगोरिया एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खरसोदखुर्द का किया औचक निरीक्षण

हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं का समय पर प्रबंधन एवं हितग्राहियों को योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने के निर्देश

उज्जैन।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विक्रम रघुवंशी, जिला उज्जैन द्वारा जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने, शासन की जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इंगोरिया एवं उप स्वास्थ्य केंद्र खरसोदखुर्द का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ. रघुवंशी ने स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध सेवाओं, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों, अभिलेखों के संधारण तथा शासन की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।



उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता बनाए रखने तथा प्रत्येक पात्र हितग्राही तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। एनआरसी में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार बेड ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करेंसीएमएचओ ने पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में बेड ऑक्यूपेंसी निर्धारित प्रोटोकॉल एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार समय पर करें प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में गर्भवती महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली गई।

सीएमएचओ ने निर्देश दिए कि शिविर में आने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला की आवश्यक जांच, स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार समय पर सुनिश्चित किया जाए। गर्भवती महिलाओं की निर्धारित 04 प्रसवपूर्व जांच समय पर पूर्ण कराई जाएं तथा उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विशेष रूप से हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान कर उनका नियमित फॉलोअप करने तथा संभावित जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं को समय रहते बर्थ वेटिंग में भर्ती कराने के निर्देश दिए, ताकि शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल एवं फॉलोअप पर जोरआशा कार्यकर्ताओं द्वारा नवजात शिशुओं की गृह आधारित देखभाल एवं नियमित फॉलोअप सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

आयुष्मान कार्ड एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें

प्रबंधनसीएमएचओ ने निर्देश दिए कि जिले की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की अद्यतन सूची रखा की जाए। संबंधित स्वास्थ्यकर्मी ऐसी महिलाओं की नियमित निगरानी करें तथा उनकी स्थिति के अनुसार समय पर उपचार एवं रेफरल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। मॉडरेट एनीमिया, गंभीर एनीमिया एवं पीआईएच (गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप) से संबंधित मामलों का निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार समय पर प्रबंधन किया जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। आयुष्मान कार्ड एवं सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करें। डॉ. रघुवंशी ने पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।

रामलीला मैदान में 1 नवंबर को 'वोट बचाओ-देश बचाओ' महारैली, राहुल ने विरोधियों को घेरा और कहा- दिल से धन्यवाद

कांग्रेस रैली का भाजपा और उनके साथी कर रहे प्रचार

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली 'वोट बचाओ-देश बचाओ' जन मार्च और महारैली से पहले भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने भाजपा और उसके सहयोगियों को रैली का प्रचार करने के लिए धन्यवाद दिया। राहुल ने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए दिल्ली पहुंचने की अपील की।

छात्रों, किसानों, मजदूरों और युवाओं से दिल्ली पहुंचने की अपील की

नई दिल्ली । राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि देश में मतदाताओं के वोट छीने जा रहे हैं और मतदाता सूचियों से लोगों के नाम हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियम-कानून तोड़े गए और सवाल उठाने वालों पर लाठियां चलाई गईं। राहुल ने दावा किया कि इन मुद्दों पर जनता चुप नहीं बैठेगी और एक नवंबर को रैली के जरिए जवाब देगी। उन्होंने लिखा कि वोट बचाने और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई में सभी को भागीदारी करनी चाहिए। राहुल ने कहा कि वोट नागरिकों का अधिकार है और इसकी रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। कांग्रेस और विपक्षी दल मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) तथा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।

राहुल गांधी पहले भी चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और 'वोट चोरी' के आरोप लगाते रहे हैं। भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से इन आरोपों पर दिए गए जवाबों को भी इस राजनीतिक विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। एक नवंबर को रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं और अपने नेताओं को अधिक से अधिक लोगों को जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। रैली के जरिए कांग्रेस मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी में है।



सभी वर्गों से दिल्ली पहुंचने की अपील

राहुल गांधी ने छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, नौजवानों और व्यापारियों से रैली में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की चिंता करने वाले सभी लोगों को इस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए। कांग्रेस नेता ने भाजपा और उसके सहयोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे रैली का जोर-शोर से प्रचार कर रहे हैं और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि भाजपा अगले सात दिन भी इसी उत्साह और लगन से प्रचार जारी रखे।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक जन महाभियोग

इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ 'दिल्ली चलो' रैली का आयोजन करने की घोषणा की है। इस रैली से पहले, 30 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक 'जन महाभियोग' आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की मांग पर जनता का फैसला सुनाया जाएगा। गठबंधन का आरोप है कि महाराष्ट्र सहित कई एसआईआर (सिस्टेमैटिक इन्टेन्सिव रिविज़न) में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं, जिसके चलते मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जा रही है।

खड़गे ने किया सभी दलों के नेताओं से संपर्क

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन में शामिल सभी दलों के प्रमुख नेताओं से संपर्क किया है। उनसे दिल्ली में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ जुटाने की सुनिश्चितता करने को कहा गया है। गठबंधन को 1 नवंबर की रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। कांग्रेस ने भी रैली की तैयारियां तेज कर दी हैं। वेणुगोपाल ने इंदिरा भवन में पार्टी के विभिन्न विभागों और संगठनों के अध्यक्षों व प्रभारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की।

राम मंदिर के चंदे को लेकर जयराम ने भाजपा को घेरा

अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे और चढ़ावे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर मंदिर को मिले दान, श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे के आंकड़ों को लेकर सवाल किए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच कराने के बजाय उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम ने अपनी पोस्ट में कहा कि भगवान को समर्पित धन की चोरी को धार्मिक दृष्टि से महापाप माना जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चंदे और चढ़ावे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों को ट्रस्ट में शामिल किया था। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले पर जवाब देने की मांग की। जयराम ने कहा कि देश की जनता यह जानना चाहती है कि राम मंदिर निर्माण के लिए कितने करोड़ लोगों ने दान दिया और कुल कितनी राशि जमा हुई। उन्होंने आरएसएस और ट्रस्ट के हवाले से दावा किया कि 2021 के निधि समर्पण अभियान में निधि समर्पण और कॉर्पस दान मिलाकर 3,264 करोड़ रुपये जमा हुए थे। उन्होंने श्रद्धालुओं की संख्या और चढ़ावे से जुड़े आंकड़ों का भी उल्लेख किया। कांग्रेस नेता के अनुसार, वर्ष 2024 के दो महीने में 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, जबकि 2025 के महाकुंभ के दौरान करीब 10 करोड़ अतिरिक्त श्रद्धालुओं के अयोध्या आने का दावा किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एक अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच 16 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की बात कही गई।

पीएम मोदी ने काशी में किया अरविंद मिल का उद्घाटन

वायुसेना के शौर्य प्रदर्शन में भी हुए शामिल

वाराणसी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी (काशी) पहुंचे। उन्होंने यहां मिर्जामुराद के खोचवां स्थित अरविंद मिल की नई इकाई का उद्घाटन किया और इसके बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित 'विंग्स ओवर गंगा' नामक भव्य एयर शो के साक्षी बने। सुबह 10:10 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मिर्जामुराद के खोचवां स्थित अरविंद मिल पहुंचे। यहां उन्होंने मिल की नई यूनिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मिल का भ्रमण किया और कार्यरत 40 महिला कर्मियों से संवाद भी किया, उनके अनुभवों को जाना।

उन्होंने महिला कर्मियों से बातचीत कर उनके काम और मिल के संचालन के बारे में जानकारी ली। इसके बाद प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन ग्राउंड पहुंचे और फिर नमो घाट से वायुसेना दिवस की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित 'विंग्स ओवर गंगा' एयर शो को देखा। इस आयोजन को देखने के लिए सुबह से ही गंगा घाटों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। सुबह नौ बजे से ही लोग अपने स्थान लेने लगे थे और दस बजे से ही सभी की नजरें आसमान पर होने वाले विमानों के करतब पर टिकी हुई थीं।



मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रसारित 'मन की बात' के 139वें एपिसोड में देशवासियों से त्योहारों के दौरान स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों की मांग अब दुनिया के विभिन्न देशों में बढ़ रही है। बिहार के पूर्णिया का मखाना ग्रीस पहुंच रहा है, कर्नाटक के कलबुर्गी की अरहर दाल मालदीव तक पहुंच रही है। इससे भारतीय किसानों और स्थानीय उत्पादकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में नए अवसर खुल रहे हैं।

फटाफट खबरें

जेडीयू से निकाले गए अनंत बोले- कुत्ता नहीं पूछेगा

जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मोकामा के विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी (पूर्व विधायक) को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई के तुरंत बाद अनंत सिंह का आक्रामक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब पार्टी को 'औकात पता चलेगा', और उसे 'कुत्ता भी नहीं पूछेगा'। उन्होंने जेडीयू के नौजूदा नेतृत्व पर भी तंज कसते हुए कहा कि केकड़ा-बिच्छू सब पार्टी का मालिक बन गया है। बाहुबली छवि के अनंत सिंह ने साफ किया कि उन्हें पार्टी से निकाले जाने का कोई अफसोस नहीं है और वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने कहा, पार्टी उनका है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कहने भी नहीं जा रहे हैं कि हमको रखिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम उचित काम किए हैं। उचित पर पार्टी निकालता है तो इस पर हमको कुछ नहीं कहना है।

भाजपा में अकेले लड़ने की अंदरूनी मांग तेज

पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा इस बार जहां अपने लिए बेहतर संभावनाएं देख रही है, वहीं गठबंधन को लेकर उसकी उलझनें बरकरार हैं। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के पार्टी में शामिल होने और सिख नेतृत्व पर जोर देने से उत्साहित भाजपा के भीतर अब अकेले चुनाव लड़ने की मांग भी जोर पकड़ रही है। पार्टी का एक वर्ग मानता है कि भविष्य के लिए राज्य में अपने को सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों में स्थापित करने के लिए अकेले चुनाव लड़ना बेहतर होगा। अगले एक नाह में भाजपा राज्य में व्यापक फीडबैक हासिल करेगी और उसके बाद ही कोई अंतिम फैसला लेगी।

एसएसपी को कोर्ट ने दी 4 घंटे खड़े रहने की सजा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर जमानत हासिल करने और बाद में अपने वादे से मुकरने वाले एक आरोपी की जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसे हिरासत में लेने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद आरोपी को सीधे अदालत से पेश न करने पर मेरठ के एसएसपी को कोर्ट रूम में शाम 4 बजे तक खड़े रहने की सजा दी गई है, जबकि मेरठ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने यह कड़ा आदेश जमानत निरस्तीकरण अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। यह मामला मेरठ के सरधना थाने में दर्ज एक मुकदमे से जुड़ा है, जहां हाईकोर्ट ने बीते 18 मार्च को एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी थी कि वह पीड़िता से विवाह करेगा।

सॉफ्टवेयर, ऐप-एआई टूल का नाम बताने से आयोग ने किया इनकार

करीम नगर । स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) अभियान के तहत देश भर में 13 करोड़ से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए जाने को लेकर जारी भारी विवाद के बीच, भारत निर्वाचन आयोग का एक नया रुख सामने आया है। चुनाव आयोग ने आरटीआई के तहत उस सॉफ्टवेयर, ऐप या एआई टूल का नाम और संस्करण बताने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर या एआई प्लेटफॉर्म का नाम, क्या यह सिस्टम नाम हटाने के लिए ऑटोमेटिकली फ्लैग करता है।



ट्रेड सीक्रेट और आईपी से जुड़ी है और आरटीआई कानून की धारा 8(1)(डी) के तहत इसे छूट प्राप्त है। यह आरटीआई आवेदन तेलंगाना के करीमनगर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता एम. ए. मुजीब अय्यूब की तरफ से दाखिल किया गया था।

उन्होंने चुनाव आयोग से कई तीखे सवाल पूछे थे, जिनमें वोटर डेटा में गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए सॉफ्टवेयर, ऐप या एआई टूल का नाम और संस्करण बताने से साफ इनकार कर दिया है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को पकड़ने में किया गया था। आयोग ने तर्क दिया है कि यह जानकारी कमर्शियल कॉन्फिडेंस,

वायुसेना की पहुंच से कोई भी लक्ष्य दूर नहीं : एपी सिंह

एयर चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा-स्वदेशी हथियारों ने दिखाया दम

1,200 किलोमीटर चौड़े और 200 किमी. गहरे क्षेत्र में किए सटीक हमले

नई दिल्ली । भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारतीय वायुसेना की पहुंच से कोई भी लक्ष्य बाहर नहीं है। पश्चिमी मोर्चे पर 1,200 किलोमीटर की चौड़ाई और 200 किलोमीटर की गहराई तक किए गए सटीक हमलों ने वायुसेना की क्षमता साबित की है। एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने कहा कि यह अभियान वायुसेना की क्षमता-केंद्रित रणनीति की प्रभावशीलता का प्रमाण है। एयर चीफ मार्शल सिंह के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर ने देश की सुरक्षा में वायु शक्ति की निर्णायक भूमिका को फिर से स्थापित किया। वायुसेना ने केवल जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई का प्रमुख माध्यम है, बल्कि उसकी क्षमता संभावित विरोधियों को आक्रामक कदम उठाने से रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके इस बयान को पाकिस्तान के संदर्भ में भारत की सैन्य क्षमताओं के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।



पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ था अभियान

ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए थे। अभियान के दौरान भारतीय वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इस कार्रवाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव बढ़ा था।

स्वदेशी हथियारों का प्रदर्शन प्रभावी रहा

वायुसेना प्रमुख ने अभियान के दौरान स्वदेशी हथियारों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि कई स्वदेशी हथियारों ने असाधारण प्रदर्शन किया और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। उनके अनुसार, सैन्य बल को किसी एक हथियार या कार्रवाई के तरीके पर निर्भर रहने के बजाय विभिन्न विकल्पों से लैस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षमता-केंद्रित सैन्य बल के पास परिस्थितियों के अनुसार कार्रवाई करने के कई विकल्प होते हैं। इसी लचीलेपन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाबी कार्रवाई को जरूरत के मुताबिक तय करने और तनाव को बढ़ने से रोकने में मदद की।

चक्रवाती तूफान से 125 की रफ्तार से हवा चलेंगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत होकर एक बेहद खतरनाक चक्रवाती तूफान का रूप लेने को तैयार है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि 27 अक्टूबर तक यह गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जो 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा। इस दौरान 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिसकी झोंकों की गति 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के प्रभाव से ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल और कुछ अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। आईएमडी के अनुसार, यह कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है।

सऊदी में हमलों के बीच एयर इंडिया की उड़ानें निलंबित



रियाद-दम्माम सेवा 7 नवंबर तक बंद

नई दिल्ली । सऊदी अरब में नागरिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहे हमलों के बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी उड़ानों के निलंबन की अवधि बढ़ा दी है। भारतीय दूतावास के अनुसार, रियाद और दम्माम आने-जाने वाली उड़ानें 7 नवंबर तक निलंबित रहेंगी, जबकि जेद्दा के लिए दोनों एयरलाइंस की सेवाएं 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगी। इस बीच, भारत सरकार सऊदी अरब में फंसे भारतीय उमराह यात्रियों की सुरक्षित और जल्द वापसी के लिए प्रयास कर रही है। भारतीय दूतावास ने शनिवार को बताया था, कि हवाई अड्डों सहित नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमलों के मद्देनजर उड़ान सेवाओं को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया गया है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों की वापसी के लिए संबंधित एयरलाइंस तथा टूर ऑपरेटरों के साथ लगातार संपर्क में है।

एक सप्ताह में 3,000 उमराह यात्री लौटे

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि पिछले एक सप्ताह के दौरान करीब 3,000 फंसे हुए उमराह यात्री सऊदी अरब से भारत लौट चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से अधिक सामान्य उमराह यात्री भी स्वदेश वापस आए हैं। शेष यात्रियों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास वहां मौजूद भारतीय नागरिकों के संपर्क में हैं। सामुदायिक स्वयंसेवकों की मदद से जरूरतमंद लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

पहाड़ों पर बर्फबारी से घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बंद

जम्मू । जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद नियंत्रण रेखा (एलओसी) से घुसपैठ के पारंपरिक रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ की आशंकाओं को देखकर सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। सर्दियों में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए विंटर बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम तैयार किया है। इसके तहत आधुनिक उपकरणों की तैनाती के साथ जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक, योजना को कई चरणों में लागू किया जाएगा। इसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), भारतीय सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल मिलकर काम करने वाले हैं।



डेनडोंग में उत्तर कोरिया को चीन से जोड़ने वाले येलू नदी पर बने पुल पर पहुंचे शीर्ष नेता किम और चीनी पीपुल्स कंसेलटेटिव कांफ्रेंस के चेयरमैन वांग हनिंग।

प्रदर्शनकारियों को संभालने पर पुलिस को धन्यवाद देते हुए बोलीं मेलोनी-

प्रदर्शन ठीक पर हिंसा व अराजकता बर्दाश्त नहीं

रोम । इटली में महंगाई, बढ़ते सैन्य खर्च और सेना के विस्तार के विरोध में शनिवार को कई शहरों में प्रदर्शन हुए। कुछ स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव भी हुआ। इस बीच, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस तथा सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए, लेकिन नागरिकों को अपने शहरों में सुरक्षित माहौल में रहने का अधिकार भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मेलोनी ने एक्स पर एक पोस्ट में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने देश के विभिन्न शहरों और सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को बनाए रखने के लिए काम किया।

कुछ लोगों की ओर से झड़प और अव्यवस्था फैलाने की कोशिशों के बावजूद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री माटेओ पियान्टेडोसी, प्रीफेक्ट्स, क्वेस्टर्स और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कार्रवाई में समन्वय करने वाले अधिकारियों की भी सराहना की। मेलोनी ने कहा कि मंत्रिपरिषद की ओर से हाल ही में मंजूर किए गए कदमों का उद्देश्य हिंसा रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को अधिक प्रभावी साधन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सभी के लिए जरूरी है–उन लोगों के लिए भी जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो काम करते हैं और उनके लिए भी जो बिना किसी डर के अपने शहरों में रहना चाहते हैं।



रोम, बोलोग्ना और टूरिन में झड़पें

इटली के नीडिया के अनुसार, शनिवार को कई शहरों में लोगों ने बढ़ती महंगाई, सैन्य विस्तार और रक्षा बजट में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किए। रोम में प्रदर्शनकारी कैपिटल के समय पियाज्ज़ा डेला रिपब्लिका से दूह-विरोधी मार्च के लिए निकले। शाम को शहर के केंद्र में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारों और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। बोलोग्ना में भी कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। वहीं, टूरिन में प्रदर्शनकारियों ने बढ़ते सैन्य खर्च और ईंधन की कीमतों के वृद्धि का विरोध किया। वहां भी शनिवार शाम पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2027 : 10वीं 12वीं की डेटशीट जल्द होगी जारी

नई दिल्ली । लाखों छात्रों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2027 की डेटशीट किसी भी समय जारी कर सकता है। उम्मीद है कि यह परीक्षा कार्यक्रम नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत तक आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा। परीक्षाएं आमतौर पर फरवरी से अप्रैल के बीच आयोजित की जाती हैं, ऐसे में छात्र अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने से पहले परीक्षा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

सीबीएसई भारत के अलावा 28 से अधिक देशों में 250 से ज्यादा स्कूलों का संचालन करता है, जिनमें मध्य पूर्व के देश जैसे दुबई, कतर, ओमान, सऊदी अरब और सिंगापुर प्रमुख हैं। इतने बड़े पैमाने पर बिना किसी टकराव के एक सुचारु डेटशीट तैयार करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। बोर्ड की विशेषज्ञ टीम डेटशीट बनाते समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखती है। सबसे पहले, यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी छात्र के दो पेपर एक ही दिन न पड़ें, खासकर 12वीं कक्षा में जहां विभिन्न विषयों के संयोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त, भौतिकी, गणित और लेखाशास्त्र जैसे कठिन विषयों के बीच छात्रों को तैयारी और पुनरावृत्ति के लिए 3 से 5 दिनों का पर्याप्त अंतर दिया जाता है।



कप्तानी छोड़ने के बाद हरमनप्रीत कौर का बल्ला गरज रहा

टी20 के बाद वनडे में भी ठोका शतक

मिताली राज को पीछे छोड़ बनाया खास रिकॉर्ड

हरमनप्रीत कौर का यह महिला वनडे क्रिकेट में आठवां शतक है। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने 232 मैचों के वनडे करियर में सात शतक लगाए थे। हरमनप्रीत ने अपने 166वें वनडे मुकाबले में यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय महिला क्रिकेट में शतक लगाने के मामले में अब वह स्मृति मंधाना के बाद दूसरे स्थान पर हैं। महिला वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के शतकों की सूची में स्मृति मंधाना 14 शतकों के साथ शीर्ष पर हैं। हरमनप्रीत कौर आठ शतकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई हैं, जबकि मिताली राज सात शतकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। पूनम राउत, जेमिमा रोड्रिग्स और प्रतिका रावल के नाम तीन-तीन शतक दर्ज हैं।

वडोदरा।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर का शानदार फॉर्म जारी है। कप्तानी छोड़ने के बाद उनके बल्ले से लगातार बेहतरीन पारियां देखने को मिल रही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज में तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद हरमनप्रीत ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में भी शतक जड़ दिया। बीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में जिम्मेदारी संभाली और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना बिना खाता खोले आउट हो गईं, जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरीं शेफाली वर्मा भी केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। शुरुआती झटकों के बाद भारतीय टीम दबाव में नजर आ रही थी। ऐसे समय में हरमनप्रीत कौर ने क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की और पारी को संभाला।

हरमनप्रीत ने शानदार शॉट लगाते हुए रन गति को बनाए रखा। उन्होंने प्रतिका रावल के साथ तीसरे विकेट के लिए 124 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इस साझेदारी ने भारतीय पारी को स्थिरता दी और टीम को शुरुआती झटकों से उबरने में मदद की। हरमनप्रीत ने 101 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उनकी शतकीय पारी में 12 चौके शामिल रहे।

टी20 सीरीज में भी दिखाया था तूफानी अंदाज

हरमनप्रीत का शानदार प्रदर्शन केवल वनडे तक सीमित नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में भी उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी की थी। उस मैच में हरमनप्रीत ने महज 41 गेंदों पर नाबाद 91 रन बनाए थे। उनकी इस पारी ने दिखाया कि वह छोटे प्रारूप में भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं। टी20 में शानदार प्रदर्शन के बाद वनडे में शतक लगाकर हरमनप्रीत ने अपनी लय बरकरार रखी है। लगातार दो प्रारूपों में उनके बल्ले से निकली बड़ी पारियां भारतीय टीम के लिए सकारात्मक संकेत हैं। खास बात यह है कि कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद वह अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान देती नजर आ रही हैं।



विश्व कप जीतने के बाद छोड़ी थी कप्तानी

जिम्बाब्वे के भारत दौरे से पहले हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि वह कप्तानी जारी रखना चाहती थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के फैसले के बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। हालांकि, कप्तानी में बदलाव के बावजूद उनकी बल्लेबाजी पर इसका नकारात्मक असर दिखाई नहीं दे रहा है। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने पिछले साल वनडे विश्व कप का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इसके बाद स्मृति मंधाना को टीम की कप्तानी सौंपी गई। अब हरमनप्रीत एक बल्लेबाज के रूप में टीम के लिए अहम योगदान दे रही हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में 91 रनों की नाबाद पारी और वनडे में शतक उनके मौजूदा फॉर्म की कहानी बयां करते हैं। भारतीय टीम को उम्मीद होगी कि हरमनप्रीत का यह शानदार प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और वह अपनी बल्लेबाजी से टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगी।

टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज 16 रन पर ढेर

बेन डकेट ने अकेले संभाला मोर्चा; पाकिस्तान के खिलाफ ठोका शतक

लाहौर।

पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई सीरीज के चौथे मुकाबले में इंग्लैंड की टीम का टॉप ऑर्डर बुरी तरह लड़खड़ा गया। शुरुआती चार बल्लेबाज मिलकर केवल 16 रन बना सके, लेकिन सलामी बल्लेबाज बेन डकेट ने एक छोर संभालते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने दबाव के बीच शानदार शतक लगाकर इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश की।

इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। टॉम बैंटन पहले ही ओवर में 4 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद जो रूट 5, हैरी ब्रूक 1 और जॉर्डन कॉक्स केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावरप्ले के दौरान ही इंग्लैंड ने अपने चार विकेट गंवा दिए, जिससे टीम मुश्किल में आ गई। लगातार विकेट गिरने के बावजूद बेन डकेट ने धैर्य नहीं खोया और रन बनाने का सिलसिला जारी रखा।

104 गेंदों में पूरा किया शतक

शुरुआती विकेट गिरने के बाद बेन डकेट को सैम करन का साथ मिला। डकेट ने 54 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद पारी को आगे बढ़ाते हुए 104 गेंदों पर शतक जड़ दिया। यह उनके वनडे करियर का पांचवां शतक और पाकिस्तान के खिलाफ पहला शतक रहा।



डकेट ने ऐसे समय में शतक लगाया, जब इंग्लैंड के छह बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। टीम के बाकी बल्लेबाजों का योगदान बेहद सीमित रहा और डकेट अकेले संघर्ष करते नजर आए। गेंदबाजों की मददगार पिच पर उन्होंने 111 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और दो छक्कों की मदद से 105 रन बनाए।

बेन डकेट की शानदार पारी का अंत पाकिस्तान के स्पिन ऑलराउंडर अराफात मिन्हास ने किया। डकेट 187 रन के कुल स्कोर पर सातवें बल्लेबाज के रूप में आउट हुए। उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी निचले क्रम के बल्लेबाजों पर आ गई।

इंग्लैंड की टीम 201 रन तक पहुंची, तब तक उसके नौ विकेट गिर चुके थे। शुरुआती बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद डकेट ने अपनी पारी से मुकाबले में इंग्लैंड को संभालने की कोशिश की। अब टीम की उम्मीदें निचले क्रम के बल्लेबाजों पर टिकी थीं, ताकि स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचाया जा सके।

पाकिस्तान की हरी जर्सी की जगह पिंक ड्रेस

इंग्लैंड के खिलाफ ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता का संदेश दे रही टीम

नई दिल्ली।

पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे ट्राई सीरीज के मुकाबले में अपनी पारंपरिक हरी जर्सी की जगह गुलाबी जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह खास पहल की है। अक्टूबर को दुनियाभर में ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। इसी अभियान के तहत पाकिस्तान की टीम ने पिंक जर्सी पहनकर लोगों को समय पर जांच कराने और बीमारी के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।



पीसीबी ने पिंक रिबन ब्रेस्ट कैंसर ट्रस्ट हॉस्पिटल के साथ मिलकर इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाया है। इसका उद्देश्य ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लोगों को जानकारी देना और समय रहते इसकी पहचान व जांच के महत्व को समझाना है। क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के जरिए इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।

पाकिस्तान के खिलाड़ियों की गुलाबी जर्सी इस अभियान का मुख्य आकर्षण रही। आमतौर पर हरी जर्सी में नजर आने वाली टीम का यह बदला हुआ अंदाज लोगों का ध्यान खींच रहा है। यह पहल केवल जर्सी के रंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

इंग्लैंड की टीम भी अभियान में शामिल

इस अभियान में केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड की टीम भी सहयोग कर रही है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों, मैच अधिकारियों और कमेंटेटरों ने गुलाबी रिबन लगाकर ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता का समर्थन किया। मुकाबले के दौरान स्टंप्स भी गुलाबी रंग के रखे गए हैं। इसके अलावा स्टेडियम की स्क्रीन और विज्ञापन बोर्ड पर भी जागरूकता से जुड़े संदेश दिखाए जा रहे हैं।

इस तरह क्रिकेट के मैदान को जागरूकता का मंच बनाया गया है, ताकि मैच देखने वाले दर्शकों तक भी यह संदेश पहुंचे कि ब्रेस्ट कैंसर की समय पर पहचान और जांच बेहद महत्वपूर्ण है।

पाकिस्तान की नजर फाइनल में जगह बनाने पर

पिंक जर्सी में मैदान पर उतरी पाकिस्तान की टीम की नजर मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर भी है। इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। पाकिस्तान ने अपने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते थे और लगातार तीसरी जीत के साथ फाइनल का टिकट हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरा। दूसरी ओर, इंग्लैंड की टीम को अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उसके लिए यह मैच काफी अहम था। फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इंग्लैंड को जीत की जरूरत थी।

पिछली भिड़ंत में पाकिस्तान ने दी थी शिकस्त

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच पिछली भिड़ंत में पाकिस्तानी टीम ने 87 रन से जीत दर्ज की थी। वहीं, इंग्लैंड को श्रीलंका के खिलाफ भी हार का सामना करना पड़ा था। उस मुकाबले में इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक के दोहरे शतक की मदद से 429 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था, लेकिन श्रीलंका ने आखिरी ओवर में लक्ष्य हासिल कर मुकाबला जीत लिया। ऐसे में इस मैच में दोनों टीमों के लिए अलग-अलग चुनौतियां थीं। पाकिस्तान जहां अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहता था, वहीं इंग्लैंड की कोशिश हार के सिलसिले को रोककर फाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखने की थी।

13 साल की ओजस्वनी सारस्वत का बड़ा सपना

नीरज चोपड़ा की तरह बनना चाहती हैं दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी

नई दिल्ली।

भारतीय गोल्फ की उभरती खिलाड़ी ओजस्वनी सारस्वत ने महज 13 साल की उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। उन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर के टूर्नामेंट 'विमेंस इंडियन ओपन' में कट हासिल कर ऐसा करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला गोल्फर बनने का गौरव हासिल किया। अब उनका सपना दुनिया की नंबर-1 खिलाड़ी बनने के साथ ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है।



ओजस्वनी ने अपने इस सपने के लिए ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को प्रेरणा बताया। उन्होंने कहा कि नीरज की मानसिकता और उनकी उपलब्धियों से उन्हें काफी प्रेरणा मिलती है। वह भी एक दिन भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना चाहती हैं।

ओजस्वनी ने बताया कि विमेंस इंडियन ओपन में कट हासिल करना उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने अपने प्रदर्शन का श्रेय स्विंग में किए गए बदलावों और खेल पर ध्यान केंद्रित रखने को दिया। दूसरे राउंड में सात बर्डी हासिल करने से उन्हें काफी फायदा मिला।

ओजस्वनी रोजाना 5 से 6 घंटे गोल्फ का अभ्यास करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस खेल से बेहद लगाव है और गेंद को हवा में उड़ते देखना ही उन्हें खुशी देता है। उनकी ताकत पुटिंग और ड्राइवर शॉट्स हैं। कम उम्र में मिली इस सफलता के बाद अब उनकी नजरें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन करने पर हैं।

मनोरंजन

जेलर 2 ने बाहुबली को पछाड़ा, 666 करोड़ की कमाई के साथ टॉप-20 में एंट्री

79 दिन बाद भी हनुमान अंश का जलवा

मुंबई।

बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 का जलवा बरकरार है। रिलीज के 10वें दिन भी फिल्म ने शानदार कमाई करते हुए दुनियाभर में 666 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। इसी के साथ फिल्म ने कमाई के मामले में बाहुबली को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की टॉप-20 सूची में जगह बना ली है।



सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, जेलर 2 ने दूसरे शनिवार को भारत में करीब 24.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 373 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 436.80 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 229.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। दुनियाभर में इसकी कुल कमाई 666.30 करोड़ रुपये बताई जा रही है।



दूसरी ओर, फिल्म हनुमान अंश भी लंबे समय से सिनेमाघरों में दर्शकों को आकर्षित कर रही है। रिलीज के 79वें दिन फिल्म ने करीब 19 लाख रुपये की कमाई की। फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन 341.26 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 402.72 करोड़ रुपये हो गया है। दुनियाभर में इसकी कमाई 451.52 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

फिल्म की लगातार कमाई को देखते हुए इसे बड़ी ब्लॉकबस्टर माना जा रहा है। निर्माताओं ने इसके सीक्वल की घोषणा भी कर दी है। जहां जेलर 2 नए रिकॉर्ड बना रही है, वहीं हनुमान अंश का लंबा बॉक्स ऑफिस सफर भी चर्चा में बना हुआ है।

मध्यप्रदेश कुमावत क्रिकेट लीग

एमपी कुमावत क्रिकेट लीग का भव्य आगाज

पहले दिन मंदसौर रॉयल की धमाकेदार जीत

इंदौर।





जिस तरह मध्यप्रदेश का स्लोगन है खेलों में बनेगा नया मध्यप्रदेश उसी तरह खेलेगा कुमावत, जीतेगा मध्यप्रदेश के सकारात्मक संदेश के साथ कुमावत समाज द्वारा आयोजित ऐतिहासिक %एमपी कुमावत क्रिकेट लीग% का रविवार से इंदौर में भव्य शुभारंभ हुआ। समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय समाजसेवी नानुराम कुमावत के संयोजन में आयोजित यह स्पर्धा देश और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रही है, जहाँ कुमावत समाज के हजारों लोग एक ही मंच पर एकत्र हो रहे हैं। पहले दिन शुरुआत मुकाबले में मंदसौर रॉयल ने श्रीराम इलेवन सिमरोल को आसानी से पराजित कर जीत के साथ शुरुआत की ।

यह टूर्नामेंट 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक बाईपास स्थित भंडारी फार्म के पीछे युग क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में खेला जा रहा है। आयोजन में प्रदेशभर से 32 टीमें भाग ले रही हैं, जिनमें लगभग 600 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स शामिल हो रहे हैं। पहले दिन हुए पहले मुकाबले में मंदसौर रॉयल ने श्रीराम इलेवन सिमरोल को 114 रनों से पराजित किया। मंदसौर इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 7 विकेट पर 153 रन बनाए। जवाब में श्रीराम इलेवन सिमरोल की टीम 39 रन पर सिमट गई । मंदसौर टीम के मानस कुमावत ने 15 गेंदों पर 40 रन बनाए और 2 विकेट भी लिए, उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया ।

प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ मोयरा सरिया के श्री निखिल उपाध्याय के मुख्य आतिथ्य में हुआ । शुभारंभ अवसर पर प्रदेश भर से भाग ले रही 32 टीमों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया । साथ ही आकर्षक ट्रॉफी का अनावरण किया गया । इस अवसर पर स्वागत उद्बबोधन देते हुए मध्यप्रदेश कुमावत क्रिकेट लीग के संयोजक नानुराम कुमावत ने कहा कि आज के युवाओं को खेल के मैदान से जोड़ने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का यह सबसे बेहतरीन माध्यम है । वर्तमान दौर में बच्चे मोबाइल और नशे की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं, जबकि उन्हें अपने शरीर और उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मैदान पर आना होगा । इसलिए यह क्रिकेट टूर्नामेंट हमने आयोजित किया है । इस टूर्नामेंट के माध्यम से हम समाज को एकत्रित करने के साथ देश-प्रदेश में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराना चाहते है । इस अवसर पर विशेष रूप से सतीश देवाल, मनोहर कुमावत, राधेश्याम सिंदड़, मरली प्रजापत, धर्मेंद्र कुमावत, भगवादासहाय कुमावत, हीरालाल कुमावत, पांचूराम कुमावत उपस्थित थे। अतिथि स्वागत मनोज कुमावत, पंकज कुमावत, अशोक कुमावत, बाबूलाल कुमावत, कविंद्र कुमावत, जितेंद्र कुमावत एवं कमल कुमावत ने किया । पूरे समाज में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है ।

टूर्नामेंट से जुड़े शैलेंद्र जांगड़ व लीलाधर दोराया ने बताया कि इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह है कि कुमावत समाज के इतिहास में पहली बार महिलाएं भी मैदान पर उतरेंगी, जिनके बीच फ्रेंडली मैच खेला जाएगा। इसके अलावा युवाओं में उत्साह भरने के लिए अंडर-18 श्रेणी और समाज के वरिष्ठजनों के लिए भी मैत्रीपूर्ण मुकाबलों का आयोजन किया गया है। बाहर से आने वाले सभी खिलाड़ियों और अतिथियों के लिए रहने व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था आयोजन समिति द्वारा की गई है।

प्रतियोगिता में विजेताओं के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। प्रथम पुरस्कार (विजेता टीम) को 1,71,000 रुपए की इनामी राशि दी जाएगी । वहीं द्वितीय पुरस्कार उपविजेता टीम को 71,000 रुपए की राशि दी जाएगी । मैन ऑफ द सीरीज को 21,000 तथा बेस्ट बॉलर एवं बेस्ट बैट्समैन को 11,000 - 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी । प्रतियोगिता के लीग मुकाबले 12-12 ओवर के खेले जाएंगे, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला 15-15 ओवर का होगा।

59 हजार करोड़ खर्च का हिसाब नहीं,51 किमी के बाईपास से कैंसर का खतरा

मास्टर प्लान का ड्राफ्ट दोबारा जारी करने की मांग, कांग्रेस ने भी दर्ज कराई आपत्ति





भोपाल आरएचएम। राजधानी के मास्टर प्लान के प्रारूप पर अब कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता अभय दुबे ने संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि विकास योजना का प्रारूप कानूनी खामियों से भरा है। इसमें सार्वजनिक परिवहन, सस्ते आवास, पानी की उपलब्धता और बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों के मुकाबले वाहनों की आवाजाही और शहर के विस्तार पर ज्यादा जोर दिया गया है। जबकि इंटरनेशनल स्टडीज हैं कि इतने चौड़े रोड के इर्द-गिर्द अगर इतनी घनी आबादी रखोगे, तो नागरिकों में कैंसर तक होने की संभावना होती हैं। दुबे ने कहा कि भोपाल की पिछली विकास योजना 2005 में समाप्त हो चुकी है। इसके बाद से शहर करीब 21 साल से नई प्रभावी विकास योजना के इंतजार में है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में भोपाल विकास योजना 2031 का प्रारूप प्रकाशित किया था। इस पर 3 हजार से अधिक आपत्तियों की सुनवाई भी पूरी हो चुकी थी और केवल अंतिम अधिसूचना जारी होना बाकी था। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उस योजना को निरस्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि मास्टरप्लान प्रारूप पर करीब 10 हजार आपत्तियां आ चुकी हैं अब इनकी छंटनी और सुनवाई में ही करीब एक महीना लगेगा। इस बीच मास्टर प्लान का ड्राफ्ट दोबारा जारी करने की मांग करते हुए दुबे ने कहा कि इसमें सार्वजनिक परिवहन, सस्ते आवास और जल प्रबंधन को शामिल करना चाहिए। प्रारूप में कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि धारा 15 के तहत 2024 के भूमि उपयोग मानचित्र का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन उनके मुताबिक, इसका विधिवत प्रकाशन, आपत्तियां आमंत्रित करने और अंगीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। भोपाल के 18 जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों को लेकर व्यापक संरक्षण योजना बनाई जानी चाहिए जबकि केवल बड़े तालाब के जलग्रहण क्षेत्र को शामिल किया गया है। 2005 की योजना के हरित क्षेत्रों और ग्रीन बेल्ट में हुए बदलावों का तुलनात्मक विवरण भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 51 किमी लंबे बायपास के दोनों ओर 300-300 मीटर के दायरे में हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल और मिक्स्ड लैंड यूज का प्रावधान है। यहां घनी आबादी बसाने से बाईपास का उद्देश्य प्रभावित होगा। उन्होंने दावा किया कि चौड़ी सड़कों के आसपास घनी आबादी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह शहर के विस्तार के खर्च 59 हजार करोड़ की वित्तीय योजना भी नहीं बताई जा रही है।

सार्वजनिक परिवहन का लक्ष्य नहीं : अभय दुबे ने कहा कि करीब 45 लाख आबादी के अनुमान पर तैयार योजना में सार्वजनिक परिवहन को लेकर स्पष्ट लक्ष्य नहीं हैं। उनके मुताबिक, भोपाल में 54 प्रतिशत यात्राएं पैदल, साइकिल या ऑटो से होती हैं, लेकिन प्रारूप में बस नेटवर्क, साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए निर्धारित क्षेत्रों की स्पष्ट योजना नहीं दिखाई गई है। मेट्रो के दोनों ओर 500 मीटर के दायरे में करीब 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के तहत शामिल करने पर भी सवाल उठाते हुए दुबे का कहना है कि इस क्षेत्र में घनत्व, प्लेयर एरिया रेशियो किफायती आवास और पार्किंग सीमा जैसे जरूरी प्रावधानों को बाद की योजनाओं पर छोड़ दिया गया है।

कांग्रेस एसआईआर के खिलाफ नहीं बल्कि इसके तरीकों के विरोध में

वरिष्ठ नेता थोराट ने भोपाल में कहा

भोपाल। एसआईआर को लेकर जारी आंदोलन व एक नवंबर को दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस के कई नेता देश में अलग अलग जगह जाकर इस बारे में अपने काडर व मीडिया से बात कर रहे हैं। इस कड़ी में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और एआईसीसी सदस्य बालासाहेब थोराट ने भोपाल में कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार भाजपा के पक्ष में काम कर रहे हैं और भाजपा का राज बचाने के लिए काम कर रहे हैं। थोराट ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के खिलाफ नहीं, बल्कि गलत तरीके से हो रही प्रक्रिया के खिलाफ लड़ रही है। यह लड़ाई लोकतंत्र और वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए है। थोराट ने कहा कि भाजपा एसआईआर के फायदे गिना रही है, क्योंकि उसे इससे फायदा नजर आ रहा है। कांग्रेस ऐसी प्रक्रिया चाहती है, जो निष्पक्ष और सही हो। उन्होंने कहा कि पार्टी गलत तरीके से एसआईआर किए जाने के खिलाफ संघर्ष करेगी। अब जनता राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में कांग्रेस के साथ है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस 1 नवंबर को रैली निकालेगी। इसके बाद नवंबर में बूथ स्तर पर जाकर मतदाता सूची की जांच की जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता देखेंगे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है। थोराट ने कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के जवाब पर भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अभियान को लेकर थोराट ने कहा कि भाजपा संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रही है,भाजपा ने अपने अभियान में 'भीड़तंत्र हटाओ' शब्द को बदलकर 'अराजकता हटाओ' कर दिया है। थोराट ने इसे कांग्रेस के आंदोलन के प्रभाव से जोड़ते हुए दावा किया कि भाजपा ने भीड़ की मौजूदगी को स्वीकार किया है। '



'मन की बात' से बनते राष्ट्र निर्माण के साझा संकल्पः राज्यपाल पटेल

विद्यार्थियों से परिसर में पेड़ लगाने का किया आह्वान

भोपाल आरएचएम। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम देश के विचार, संकल्प और सामर्थ्य का सबसे सशक्त प्रेरणादायी मंच है। कार्यक्रम को सुनना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचार, ज्ञान और अनुभवों से प्रेरणा लेने और सकारात्मक बदलावों के साथ राष्ट्र निर्माण के नए साझा संकल्पों को दिशा देने का अवसर है। उन्होंने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बताते हुए प्रतिमाह वसुंअली निरंतर देश की जनता के बीच प्रधानमंत्री के पहुंचने को अभूतपूर्व बताया है। राज्यपाल रविवार को स्थानीय भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण से पूर्व विद्यार्थियों से चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल ने विद्यार्थियों का आह्वान किया है कि वे परिसर में एक पेड़ लगा कर संस्थान से जाएं, इससे संस्थान के साथ उनका जुड़ाव मजबूत होगा। राज्यपाल ने कार्यक्रम के बाद विद्यार्थियों से उनका परिचय प्राप्त किया, उन्हें शुभाशीष प्रदान किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया नर्मदापुरम की शिवानी के अंगदान का उल्लेख

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के नर्मदापुरम की शिवानी के अंगदान का उल्लेख किया। कार्यक्रम के 139 वें एपिसोड में उन्होंने देश में मेडिकल क्षेत्र में हो रही शोध और नवाचार पर चर्चा करते हुए कहा कि एडवांस रिसर्च में आर्गन डोनेशन की अहम भूमिका होती है। ऐसे लोग जो अपना जीवन पूरा करने के बाद आर्गन डोनेट करके जाते हैं, वो कितने ही लोगों का जीवन भी बचाते हैं और रिसर्च को भी संभव बनाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है - मध्यप्रदेश में नर्मदापुरम की सुश्री शिवानी का है। शिवानी के सड़क दुर्घटना की शिकार होने पर परिवार ने कठिन समय में भी ऐसा निर्णय लिया, जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह फैसला था सुश्री शिवानी के अंग दान का। उनके परिवार के इस फैसले से समाज और देश के लिए एक बड़ा संदेश गया है। मानवता के ऐसे एक कदम से किसी परिवार में खुशियां फिर से लौट सकती हैं और साथ ही रिसर्च के कामों में भी मदद मिलती हैं। नर्मदापुरम की शिवानी का मन की बात कार्यक्रम में उल्लेख करने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में यह कार्यक्रम सुना।

पेंशन अपडेट करने का झांसा देकर रिटायर्ड इंजीनियर के खाते से निकाले 7.80 लाख

भोपाल,आरएचएम। पेंशन अपडेट कराने और ऑनलाइन सुविधाएं देने का झांसा देकर साइबर जालसाज ने एक रिटायर्ड इंजीनियर को 7 लाख 80 हजार रुपए का चूना लगा दिया। आरोपी ने लिंक भेजकर फरियादी से आधार कार्ड और पेन कार्ड के अलावा अन्य जरूरी जानकारी हासिल कर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर दी। पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपी के मोबाइल नंबर और जिन खातों में राशि ट्रांसफर हुई है, उनकी जानकारी निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक वेस्टर्न कोर्ड कॉलोनी कोलार निवासी अनिल कुमार (66) रिटायर्ड इंजीनियर है। उन्हें पेंशन मिलती है। विगत 21 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात जालसाज ने कॉल कर बताया कि सरकार के नए नियमों के तहत आपकी पेंशन अपडेट होना है। उसके लिए कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, अन्यथा आपको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी या आपका पेंशन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। पेंशन अपडेट होने से आपको सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलने लगेंगी। फरियादी अनिल कुमार अपना पेंशन कार्ड अपडेट कराने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद जालसाज ने उन्हें एक लिंक भेजा। फरियादी ने आरोपी जालसाज के कहे अनुसार लिंक खोलकर उसमें आधार कार्ड और पेन कार्ड सहित अन्य जरूरी जानकारी भर दी। बताया जा रहा है कि उसके कुछ देर बाद ही फरियादी अनिल कुमार के खाते से दो बार में 4 लाख 90 हजार और 2 लाख 90 हजार कुल 7 लाख 80 हजार रुपए कट गए। मोबाइल में पैसे कटने का मैसेज आने के बाद उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

जहरीली नहीं होने देंगे जल-जमीन



भोपाल,आरएचएम। रीवा न्यूक्लियर प्लांट के विरोध में कांग्रेस ने रविवार को व्यापमं चौराहे पर धरना दिया। दिलीप तिवारी सहित अनेक कांग्रेसियों ने यहां प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आशंका जताई कि न्यूक्लियर प्लांट से जल और जमीन पर भी जहरीली हो सकती है। इससे पर्यावरण को खतरा बढ़ेगा, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। धरने में सरकार से न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बजाय क्षेत्र में रोजगार के साधन विकसित करने की मांग की गई।

कृषि भूमि की रजिस्ट्री के नाम पर हड़पे 30 लाख,आरोपी गिरफ्तार

भोपाल,आरएचएम। कृषि भूमि की रजिस्ट्री कराने का अनुबंध कर 30 लाख रुपये लेने के बाद न तो जमीन की रजिस्ट्री कराई और न ही रकम वापस की। गुनगा थाना पुलिस ने शिकायत की जांच और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, महेंद्र टाउनशिप फेज-2, बावड़िया कलां निवासी दीपक मिश्रा ने 8 अगस्त 2026 को मामले की शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम पीपलखेड़ा में स्थित दो भूखंडों की कुल 2.577 हेक्टेयर यानी करीब 6.36 एकड़ कृषि भूमि के विक्रय के संबंध में आरोपी लक्ष्मण सिंह राजपूत के साथ अनुबंध हुआ था। अनुबंध के तहत फरियादी ने 30 लाख रुपये बयाना राशि के रूप में दिए थे। फरियादी ने 15 लाख रुपये चेक के माध्यम से और शेष 15 लाख रुपये नकद दिए थे। रकम लेने के बावजूद आरोपी ने भूमि की रजिस्ट्री नहीं कराई। फरियादी द्वारा रकम वापस मांगे जाने पर भी उसे पैसे नहीं लौटाए गए। इसके बाद पुलिस ने शिकायत की जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने विक्रय अनुबंध, बैंक स्टेटमेंट और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। इसके आधार पर पुलिस से धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

पूछताछ में रकम खर्च करना बताया: पुलिस को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी लक्ष्मण सिंह राजपूत (44), निवासी ग्राम पीपलखेड़ा, थाना गुनगा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने प्राप्त रकम खर्च करना बताया। पुलिस ने आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

आलोक श्रीवास्तव कायस्थम के प्रभारी महासचिव नियुक्त

भोपाल आरएचएम। कायस्थ समाज की अग्रणी संस्था कायस्थम की वार्षिक आमसभा की बैठक में सयुंक्त सचिव अजय भटनागर ने आगामी एक वर्ष के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। महासचिव रश्मि सक्सेना द्वारा त्यागपत्र देने के बाद सचिव आलोक श्रीवास्तव को महासचिव का प्रभार सौंपने का निर्णय लिया भी लिया गया। कायस्थम अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने बताया कि आगामी जनवरी माह में रवींद्र भवन में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा।



भोपाल। लाल परेड मैदान पर रावतपुरा सरकार के कार्यक्रम के लिए तैयारी।

मध्यप्रदेश में कोचिंग सेंटरों के लिए अब कड़े नियम सीसीटीवी, मेंटल और कैरियर काउंसलिंग भी जरूरी

भोपाल आरएचएम। मध्यप्रदेश में कोचिंग सेंटरों के कड़े नियम लागू किए गए हैं। उन्हें न केवल अपनी फीस सार्वजनिक करनी होगी बल्कि मेंटल औरकैरियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। निजी स्थानों को छोड़कर पूरी कोचिंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। इसके लिए राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र (पंजीयन एवं विनियमन) नियम, 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियमों में कोचिंग सेंटर को अपनी वेबसाइट पर फीस, शिक्षकों, सुविधाओं जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करना अनिवार्य किया गया है। कोचिंग की रजिस्ट्रेशन की अवधि 3 साल के लिए होगी और इसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन ट्रांसफरेबल नहीं रहेगा। कोचिंग की एक से अधिक ब्रांच होने पर उसे एक अलग सेंटर माना जाएगा। कोचिंग में जिस परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी उसके संबंध में फीस का पूरा स्ट्रक्चर भी जाहिर करना होगा।

संवेदनशील स्थानों की रिकॉर्डिंग नहीं: कोचिंग में शौचालय, चेंजिंग रूम और परामर्श कक्ष जैसे संवेदनशील स्थानों को छोड़कर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे मानसिक स्वास्थ्य और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया गया है। कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाने, स्टूडेंट पर पढ़ाई के दबाव को समझने और शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था तैयार करने के लिए ये सख्त प्रावधान किए गए हैं।



कोर्ट पेशी में पुलिस का वीआईपी ट्रीटमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

भोपाल,आरएचएम। नशे से दूरी है जरूरी अभियान के बारे में और पुलिस का स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में जब कोर्ट पेशी के दौरान मुल्जिम सड़क पर हथकड़ी पहने खुलेआम सिगरेट पीता नजर आए तो पुलिस की जिम्मेदारी और काम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर 25 अक्टूबर को ऐसा ही एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक मुल्जिम कोर्ट के बाहर सिगरेट पीता नजर आया है। उसके एक हाथ में हथकड़ी थी और दूसरे हाथ में सिगरेट थी। वीडियो में दो प्रधान आरक्षक नजर आए हैं। एक प्रधान आरक्षक पान की गुमटी पर पैसे देते हुए नजर आ रहा है। जबकि एक महिला मुल्जिम से बातचीत करती हुई नजर आ रही है। हैरानी की बात तो यह भी है कि मुल्जिम मोबाइल पर बातचीत कर रहा है। कोर्ट पेशी के दौरान प्रधान आरक्षकों के सामने सिगरेट पीना और मोबाइल पर बातचीत करने के इस वीडियो ने एक बार साबित कर दिया है कि पैसों से सबकुछ हो सकता है। मुल्जिम के कोर्ट पेशी के दौरान मोबाइल पर बातचीत करने से पुलिस एक्ट की नियमों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही मुल्जिम को कोर्ट पेशी के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट देने से पुलिस की छवि धूमिल हुई है। वायरल वीडियो आलाधिकारियों तक पहुंच गया है। बताया जाता जा रहा है हेड कांस्टेबल कमला नगर थाने के हैं और मुल्जिम भी वहीं का है।

बायपास पर 1.50 लाख की एमडी ड्रग्स के साथ दो युवक गिरफ्तार

बाइक-मोबाइल समेत 3 लाख का मशरूका जब्त, दोनों पर दर्ज है कई आपराधिक मामले

भोपाल आरएचएम। परवलिया सड़क पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12.63 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई है, जिसकी कीमत करीब 1.50 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल बाइक और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। जब्त मशरूका की कुल कीमत करीब तीन लाख रुपए आंकी गई है।

पुलिस के मुताबिक, 24 अक्टूबर की रात मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो युवक मोटरसाइकिल से एमडी ड्रग्स लेकर थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। सूचना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर थाना प्रभारी के नेतृत्व में पांच पुलिस टीमें बनाई गईं। टीमों ने बायपास रोड पर घेराबंदी की। रात करीब 1.40 बजे संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार नजर आए। पुलिस को देखकर दोनों ने भागने के लिए बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। तलाशी में तरुण सराठे (24), निवासी छावनी पटार, बिलखिरिया के कब्जे से 12.63 ग्राम एमडी ड्रग्स मिली। उसके साथ अखिलेश मेहरा (24), निवासी छावनी पटार को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी तरुण के खिलाफ बिलखिरिया थाने में मारपीट और आर्म्स एक्ट के दो मामले दर्ज हैं, जबकि अखिलेश के खिलाफ मारपीट के चार प्रकरण पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपियों से ड्रग्स की सप्लाई और नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है।

युवक ने लगाई फांसी

भोपाल। टीटी नगर थाना क्षेत्र स्थित बाणगंगा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पीएम के बाद परिजन को सौंप दिया है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है। पुलिस के अनुसार आशाराम हवेलिया (40) बाणगंगा, टीटी नगर में रहते थे और बेरोजगार थे। उनकी पत्नी बंगले पर काम करने जाती है। आशाराम शराब पीने के आदी थे। परिजन ने बताया कि शुक्रवार रात उन्होंने खाना खाया और सो गए थे। शनिवार सुबह उनके पिता छत पर घूमने के लिए गए। इस दौरान उन्होंने आशाराम को छत पर बने पाइप पर फांसी के फंदे पर लटके देखा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

49 स्थायी और 51 गिरफ्तारी, वारंट तामील

भोपाल आरएचएम। भोपाल (देहात) पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार-रविवार की दरमियानी रात जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष कॉम्बिंग गश्त और वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रमोद कुमार सोनकर के मार्गदर्शन में चलाए गए इस अभियान में 91 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस दौरान 49 स्थायी वारंट और 51 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। अभियान के तहत फरार आरोपियों और वारंटियों की धरपकड़ के साथ गुंडा-बदमाशों एवं निगरानी बदमाशों की भी जांच की गई। पुलिस ने न्यायालयीन वारंटों के अलावा समंस की तामीली पर भी विशेष ध्यान दिया। अधिकारियों के निर्देश पर जिले के सभी थाना क्षेत्रों में निर्धारित कार्ययोजना के अनुसार कार्रवाई की गई। अभियान की निगरानी संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (पुलिस) ने की। कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस ने 49 स्थायी वारंट और 51 गिरफ्तारी वारंट तामील किए। इसके अलावा 46 जमानती वारंट और 43 समंस की तामीली भी की गई। पुलिस टीमों ने 37 गुंडा-बदमाशों और 25 निगरानी बदमाशों की चेकिंग की। संपत्ति संबंधी अपराधों के सिलसिले में भी एक स्थान पर जांच की गई।

आईएसबीटी पर खड़ी बसों में भीषण आग से आठ बसें जलीं

वर्मा ट्रेवल्स की सभी ट्रिप कैंसिल

भोपाल आरएचएम। राजधानी के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल आईएसबीटी पर रविवार रात भीषण आग लग गई। यहां खड़ी वर्मा ट्रेवल्स की एक बस से आग भड़की और आसपास की अन्य बसों को चपेट में ले लिया। बस स्टैंड पर आगजनी से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि करीब एक किलोमीटर दूर तक आसमान में काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा था। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में वर्मा ट्रेवल्स की 8 बसें जलीं जिनमें से 4 पूरी तरह खाक हो गईं। ये बसें सूरत, अहमदाबाद, पुणे, बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल रूट पर चलती थीं। हादसे के बाद सभी ट्रिप कैंसिल कर दी गईं।



प्रकाशक, मुद्रक, स्वत्वाधारी एवं संपादक सुनील वर्मा के लिए 1/4, परदेशीपुरा इन्दौर से प्रकाशित एवं दैनिक भास्कर प्रेस 4/54 प्रेस कॉम्प्लेस एबी रोड इंदौर मध्यप्रदेश इन्दौर से मुद्रित.
कार्पोरेट कार्यालय : 301, अरु प्लाजा एमजी रोड इन्दौर (म.प्र.) सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा। मो. : 9425491979, 7000877686, E-mail: janbhavana.ind@gmail.com